बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 133

इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश

भारत का 2030 तक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी करने तथा 2070 तक उत्सर्जन को विशुद्ध शून्य तक लाने का लक्ष्य, काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किस हद तक अपना पाते हैं। हम पहले ही खुद को दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सबसे तेज बढ़ते बाजार के रूप में स्थापित कर चुके हैं। देश की स्थिति को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने हाल ही में ई-मोबिलिटी के लिए शोध एवं विकास रणनीति को लेकर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में ईवी को व्यापक तौर पर अपनाने की बात कही गई और यह भी कहा गया कि हमें स्वदेशी ऊर्जा भंडारण व्यवस्था, चार्जिंग ढांचे के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और टिकाऊ सामग्री और रिसाइक्लिंग के तरीके तलाशने होंगे।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में देश में ईवी की सालाना बिक्री 17.5 लाख वाहनों की थी जो इससे पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी ज्यादा थी। ईवी बाजार में वृद्धि का श्रेय नैशनल ऑटो पॉलिसी 2018 और नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 को दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार की प्रमुख योजना फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड ऐंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या (फेम) 2, जो इस साल के आरंभ में समाप्त हुई, उसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों की श्रेणी को इलेक्ट्रिक बनाने पर जोर दिया गया। ये दोनों श्रेणियां इस योजना के तहत लक्षित वाहनों में 98 फीसदी वाहनों को कवर करती हैं। देश की सड़कों पर इन्हीं दोनों श्रेणियों के वाहनों का राज है।

ईवी 30 एट 30 के लक्ष्य के तहत भारत की कोशिश है कि 2030 तक देश में निजी रूप से पंजीकृत होने वाले वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 30 फीसदी, बसों में 40 फीसदी, वाणिज्यिक कारों में 70 फीसदी और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में 80 फीसदी कर दी जाए।

बहरहाल इन वाहनों का महंगा होना और चार्जिंग के लिए अपर्याप्त ढांचों का होना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा उत्पादन की बात करें तो ई-मोबिलिटी की मूल्य श्रृंखला आयात पर बहुत अधिक निर्भर करती है। घरेलू ईवी निर्माण अभी भी वाहनों की असेंबलिंग तक सीमित है और अधिकांश कलपुर्जों बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक चिप आदि के लिए हमारे पास घरेलू क्षमता नहीं है। कमजोर आपूर्ति श्रृंखला के कारण घरेलू कलपुर्जा निर्माण के लिए हम तकनीक और सामग्री के स्तर पर बहुत हद तक चीन पर निर्भर करते हैं। ई-मोबिलिटी क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वाहन क्षेत्र में घरेलू शोध क्षमताओं को मजबूत करना होगा। उदाहरण के लिए फिलहाल 70 फीसदी लीथियम हम चीन से आयात करते हैं और रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हमें सोडियम-आयन, लीथियम-एयर, एल्युमीनियम-एयर और लीथियम-सल्फर जैसे विकल्पों से नवाचार करने की कोशिश करनी चाहिए। ये लीथियम-आयन बैटरी के विकल्प बन सकते हैं। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि ई-मोबिलिटी में 30-34 अहम क्षेत्रों में शोध एवं विकास के लिए करीब 1,200 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।

फंडिंग के लिए विभिन्न सरकारी विभाग जिनमें राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय आदि सभी शामिल हैं, साथ आ सकते हैं। शोध एवं विकास में निवेश सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से आ सकता है। कुछ परियोजनाओं का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है जिन्हें आजमाया जा सकता है। इसमें लीथियम आयन बैटरी के लिए उन्नत तरल इलेक्ट्रोलाइट्स पर शोध, ईवी के लिए डायनामिक चार्जिंग व्यवस्था, बेहतर फ्यूल सेल क्षमता और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तरल ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर स्टोरेज तकनीक शामिल हैं। ईवी के निर्माण के पीछे बुनियादी विज्ञान में निवेश से भारत कुछ वर्ष बाद इस क्षेत्र की मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक कद हासिल कर सकता है। बहरहाल, जब तक हम बिजली के लिए प्रमुख रूप से ताप बिजली पर निर्भर रहेंगे तब तक कुल मिलाकर पर्यावरण संबंधी लाभ सीमित ही रहेंगे।

अजय मोहंती

बैंकों के नियमन में नियामकीय संतुलन

बैंकिंग क्षेत्र के नियमन में संतुलन की आवश्यकता है, निजी बैंकों में शीर्ष नियुक्तियों और निवेशकों के संरक्षण के हवाले से इस संतुलन की आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं अजय त्यागी और रचना बैद

दुनिया के अधिकांश देशों खासकर भारत जैसे उभरते देशों में वित्तीय क्षेत्र पर बैंकों का दबदबा है। बैंक महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अपनी पहुंच के जरिये वित्तीय समावेशन को गति देते हैं, ऋण को वांछित क्षेत्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं और सरकारों को विभिन्न लक्ष्य पाने में सहायता करते हैं।

बैंकों के लिए एक अलग नियामकीय ढांचे की जरूरत एकदम स्वाभाविक है। वे असाधारण रूप से ऊंचे लीवरेज रेश्यो पर काम करते हैं, उन्हें जनता से जमा लेने की इजाजत है और उन्हें मददगार के रूप में केंद्रीय बैंक का समर्थन हासिल है।

जनता का बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास है। बैंकों के समस्याग्रस्त होने के गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि बैंकों की निगरानी और उनका नियमन एक गंभीर काम है। दुनिया भर में बैंकिंग क्षेत्र के नियामकों को रूढ़िवादी और जोखिम से बचने वाला माना जाता है। उस लिहाज से देखा जाए तो आखिर में बैंक वाणिज्यिक इकाइयां हैं और वे मुनाफे के लिए काम करते हैं। वे न केवल आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि दूसरे ऋणदाताओं के साथ भी उनकी प्रतिस्पर्धा होती है। उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त लचीलेपन की आवश्यकता होती है, तकनीकी उन्नति के साथ कदम मिलाकर चलना होता है और नवाचार को बढ़ावा देना होता है। बैंकिंग नियामक के लिए सही नियामकीय संतुलन कायम रखना आसान नहीं होता है। उन्हें यह ध्यान रखना होता है कि कब सख्ती बरतनी है और कब नहीं। उसके बाद नियम आधारित और सिद्धांत आधारित नियमन के बीच चयन करना होता है।

भारतीय संदर्भ में बात करें तो कुछ लोग ही इस बात से असहमत होंगे कि बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक बैंकों की लगभग सभी गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखता है। औपचारिक नियामकीय निगरानी के अलावा रिजर्व बैंक बैंकों के काम पर अनौपचारिक तरीके से भी निगरानी रखता है। कई बार बैंकों को इन निर्देशों का पालन करना काफी कठिन साबित हो सकता है।

बैंकिंग नियमन की निगरानी की व्यवस्था में व्यापक विषय साबित होते हैं लेकिन इस आलेख में हम बैंकों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और बैंक प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा जैसे मुद्दों तक सीमित रहेंगे।

निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड चेयरमैन, एमडी और निदेशकों की नियुक्तियों को रिजर्व बैंक मंजूरी देता है। वह उनकी कार्यावधि और वेतन भत्तों को भी मंजूरी देता है। भले ही बैंकों का आकार कुछ भी हो। कई बार रिजर्व बैंक ने लोगों के नाम खारिज किए हैं या उनके कार्यकाल को बदला है। कई बार रिजर्व बैंक इन पदों पर होने वाली नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए बैंकों के प्रबंधन द्वारा किए गए नामों की सिफारिश को नकार देता है और उनके कार्यकाल को संशोधित करता है। इसके अलावा कई अवसरों पर नियामक बैंकों के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों को भी नियुक्त करता है।

फिलहाल बाजार पूंजीकरण के मुताबिक देश में निजी क्षेत्र के 10 बड़े बैंकों में सात के चेयरपर्सन या तो रिजर्व बैंक के पूर्व अधिकारी हैं या पूर्व अफसरशाह। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के साथ ये श्रेणियां इन बैंकों के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशकों में अच्छी खासी हिस्सेदारी रखती हैं। एक बैंक में तो यह 50 फीसदी तक है। ऐसे में निजी बैंकों का बोर्ड भी काफी हद तक सरकारी बैंकों जैसा नजर आने लगता है।

इसका एक असर यह होता है कि नियामकों और विनियमितों यानी बैंकों के बीच दूरी कम होती है। सभी बैंकों में शीर्ष पदों पर लोगों की क्षमताओं और ईमानदारी की जवाबदेही नियामक पर होने से नैतिक समस्या खड़ी होती है और यह संभावना बनती है कि कहीं नियामक ज्यादा सहनशीलता न दिखाने लगे। परिणामस्वरूप कई बार नियामक के लिए खुद को असहज करने वाली परिस्थितियों से मुक्त करना मुश्किल हो सकता है। इस प्रक्रिया में नियामक अपनी विश्वसनीयता को भी जोखिम में डाल सकता है।

रिजर्व बैंक नियुक्तियों के मामले में अपनी नीति पर नए सिरे से विचार कर सकता है और शायद वह अपनी भूमिका को महत्त्वपूर्ण बैंकों के चेयरपर्सन और निदेशकों की नियुक्ति तक सीमित कर सकता है। अब बात करते हैं निवेशकों के संरक्षण की। नियामकीय आदेश के अनुसार बैंकों का सूचीबद्ध होना आवश्यक है। इसका मकसद उनके कामकाज में पारदर्शिता लाना और कारोबारी संचालन में सुधार करना है। बहरहाल, अक्सर सूचीबद्ध बैंक समय पर या पूरा सार्वजनिक खुलासा नहीं करते। अक्सर वे ऐसा जानबूझकर करते हैं। इसके पीछे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा या वित्तीय स्थिरता से जुड़ी चिंताएं होती हैं।

ऐसे में बैंक की प्रतिभूतियों के निवेशक शायद उन बैंकों की गतिविधियों के बारे में भलीभांति नहीं जान पाएं। ऐसे में नियामक द्वारा अचानक बैंक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई निवेशकों को मुश्किल हालात में डाल सकती है। इससे भी अधिक चिंतित करने वाली बात यह है कि अक्सर रिजर्व बैंक देनदारी में चूक करने वाले बैंकों के खिलाफ कोई मुखर आदेश नहीं देता। इसके परिणामस्वरूप नियामक के कदमों के बाद अक्सर निवेशक अंदाजा लगाते रह जाते हैं कि असली मुद्दा क्या था।

निवेशकों की चिंताओं की बात जारी रखते हुए 8,400 करोड़ रुपये मूल्य के एटी-1 बॉन्ड को लेकर चल रहे विवाद को याद रखना होगा। ये बॉन्ड येस बैंक ने जारी किए थे और रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासन ने इन्हें बट्टे खाते में डालते हुए स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों के निवेश की मदद से बैंक को नए सिरे से खड़ा किया। एटी-1 बॉन्ड का ढांचा जटिल है और इन बॉन्ड को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि अगर किसी बैंक में मुश्किल हालात बनें और इन्हें बट्टे खाते में डालना हो तो ऐसा बैंक की सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी को खत्म करके ही किया जा सके।

यह दलील मददगार नहीं है कि एटी-1 बॉन्ड अंतरराष्ट्रीय मान्यता वाला है और उसे अन्य देशों के बैंक भी इस्तेमाल करते हैं तथा इसकी मदद से पूंजी जुटाते हैं।

गत वर्ष क्रेडिट सुइस बैंक के पतन की दास्तान ने भी अनेक नियामकों को ऐसे बॉन्ड पर नए सिरे से नजर डालने पर विवश किया। इस पूरी बात का अर्थ यह है कि जमाकर्ताओं के अलावा बैंक प्रतिभूतियों के निवेशक भी महत्त्वपूर्ण अंशधारक हैं और उनके हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए।

(सेबी के चेयरमैन रह चुके अजय त्यागी ओआरएफ के विशिष्ट फेलो हैं और रचना बैद एनआईएसएम की प्रोफेसर हैं)

भाजपा और विपक्ष के तनावपूर्ण रिश्ते

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों को निराशा में खुद से यह पूछने के लिए माफ किया जा सकता है कि उन्हें अच्छी खबर कब मिलेगी। पार्टी लोक सभा चुनावों में पिछले चुनाव की 303 सीट से घटकर 240 पर आने के बावजूद साझेदारों की मदद से केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद 245 में से 90 सीट के साथ अब राज्य सभा में पार्टी का बहुमत नहीं है। जुलाई के आरंभ में हुए विधान सभा उपचुनावों में भाजपा को 13 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल दो पर जीत मिली।

पार्टी की विफलताओं का क्रम अलग-अलग तरह से सामने आ रहा है लेकिन राज्यों की राजनीति में यह सबसे अधिक स्पष्ट है। 36 में से 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार है (कुछ जगह गठबंधन के साथ) और वहां सरकारें अपने बचाव में आक्रामकता दिखा रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस तथा 'इंडिया' गठबंधन के अन्य साझेदार भी अब पहले की तुलना में अधिक आक्रामक हैं। राजनीतिक और नीतिगत संघर्ष अचानक तीव्र हो गया है।

राजस्थान का उदाहरण लें तो भाजपा को 2023 के विधान सभा चुनावों में 58 फीसदी सीट पर जीत मिली। पार्टी के पास 200 में से 115 सीट हैं और उसके बहुमत पर कोई संदेह नहीं है। सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस के पास केवल 69 सीट हैं। दिसंबर 2023 से जून 2024 तक राजस्थान में विपक्ष की बात करें तो वह मोटे तौर पर सुषुप्तावस्था में नजर आया। कांग्रेस आंतरिक तनावों में उलझी नजर आई। परंतु उसके बाद हुए लोक सभा चुनावों में भाजपा को 25 में से केवल 14 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस को आठ सीट पर और अन्य दलों को तीन सीट पर जीत मिली। ऐसे में 4 जुलाई को आरंभ हुआ विधान सभा का बजट सत्र कांग्रेस की ओर से अप्रत्याशित आक्रामकता से भरा हुआ है। विपक्ष के विधायक रोज सवाल करते हैं और कामकाज को बाधित करते हैं।

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

गत सप्ताह कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग उनके इलाकों में सड़क निर्माण के पहले सलाह मशविरा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि वहां सड़क निर्माण अभी भी हारे हुए भाजपा विधायकों के इशारे पर हो रहा है। भाजपा जवाबी कार्रवाई में वही कर रही है जो उसका मूल कार्यक्रम है: सरकार एक विधेयक तैयार कर रही है जिसमें धर्मांतरण पर कठोर दंड की व्यवस्था होगी। वह 2008 में पारित एक अन्य विधेयक को हटा रही है जिसे वसुंधरा राजे सरकार ने पारित किया था लेकिन उसे कभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल सकी। राजे ने भी 2013 से 2018 के बीच दोबारा मुख्यमंत्री होने पर भी उसे वापस नहीं लाया।

ओडिशा में बीजू जनता दल के 24 साल के शासन के बाद भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला है। राज्य में पहली बार पार्टी की सरकार बनी। 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा में भाजपा को 78 सीट के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। बीजू जनता दल को केवल 51 सीट पर जीत मिली। राज्य के 21 लोक सभा क्षेत्रों में से 20 में भाजपा को जीत मिली और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई।

लंबे समय तक बीजू जनता दल कांग्रेस को अपना प्रमुख शत्रु मानता रहा। परंतु अब न केवल पार्टी ने राज्य सभा में भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है बल्कि उसने भाजपा सरकार के मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखने के लिए 'शैडो' भी नियुक्त किए हैं। इनमें से कई पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें सरकार या विधान सभा का कोई अनुभव नहीं है।

हालांकि बीजू जनता दल ने 'इंडिया' गठबंधन की ओर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है लेकिन इसमें भी बदलाव आ सकता है। भाजपा का नीतिगत रुख स्पष्ट नहीं है: क्या वह पिछली सरकार के लोकलुभावन कार्यक्रमों को जारी रखने वाली है? क्या वह नवीन पटनायक और उनके नामांकित लोगों को खारिज करने जा रही है? उड़िया पहचान को लेकर संवेदनशील राज्य में क्या सरकार डबल इंजन की बात करेगी? ऐसे में बीजू जनता दल का आरोप होगा कि ओडिशा की पहचान को खतरा है और वह भी भाजपाशासित राज्यों में से बस एक और राज्य बनकर रह जाएगा।

उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव परिणामों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बातचीत शुरू कर दी है जिनकी घोषणा कभी भी हो सकती है। अतीत में मतांतर के चलते दोनों दल विधानसभा चुनावों में साथ नहीं आए।

पंजाब में भाजपा के केवल दो विधायक हैं। परंतु लोक सभा की सीट गंवाने के बावजूद उसका मत प्रतिशत अब तक के उच्चतम स्तर पर है। यही वजह है कि पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद रवनीत बिट्टू को केंद्र में मंत्री बनाया है। हालांकि भाजपा प्रदेश में अपनी स्थिति कैसे मजबूत बनाती है यह देखना दिलचस्प होगा।

आने वाले दिनों में आर्थिक सुधार, खासकर समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। मौजूदा परिदृश्य में राजनीतिक रुख कड़े हैं और प्रतिरोध भी। ऐसे में सहमत बनाने के लिए बातचीत और नरमी की आवश्यकता होगी।

आपका पक्ष

देश में बढ़ते रेल हादसे चिंतनीय

उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की आठ बोगियां बेपटरी हो गईं। इस घटना में चार यात्रियों की मौत और 31 के घायल होने की खबर है जिनमें पांच गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय प्रशासन और रेलवे यात्रियों की मदद में जुटा रहा। अब कोई तकनीकी कारण है या साजिश अथवा रखरखाव में लापरवाही यह जांच का विषय है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे के बाद की ये शासकीय प्रक्रियाएं हैं जिससे प्रभावितों को कुछ राहत मिल सकेगी। इससे कुछ ही महीने पहले और भी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें काफी जान-माल का नुकसान हुआ है। बार-बार रेल दुर्घटना होना कहीं न कहीं लापरवाही दर्शाता है। फिर चाहे मानव की भूल हो या रखरखाव में कमी अथवा तकनीकी कारण जो कि गंभीर रूप से चिंतनीय है। हादसे में मुआवजे सहयोगी हो सकते हैं लेकिन जिनकी मौत हुई उनके परिवार वाले के जिंदगी भर के दुःख तो दूर नहीं हो सकते। रेलवे प्रशासन खामियों और रखरखाव पर ध्यान दे, ताकि हादसों की पुनरावृत्ति रुक सके और लोगों की रेल यात्रा सुखद व सुरक्षित बनी रह सके।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद शुक्रवार को रेल कर्मचारियों ने पटरी की मरम्मत की

ट्रेन दुर्घटनाओं को रोके सरकार

सरकार एक तरफ तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं। ट्रेन हादसे को रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं। रेल मंत्रालय और रेलवे के उच्च अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए और ज्यादा चुस्त होना चाहिए। ताकि भविष्य में किसी भी लापरवाही का बुरा नतीजा किसी निर्दोष को अपनी जान देकर न चुकाना पड़े। वैज्ञानिकों को ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे कोई भी ट्रेन अचानक ब्रेक लगाने पर एकदम रुक जाए, अभी तक ट्रेनों को रोकने के लिए भी इनके ड्राइवरों को मुश्किल होता है, ब्रेक लगाने पर भी ट्रेन कुछ मीटरों तक चलती रहती है। ट्रेनों में नई तकनीक विकसित कर सुरक्षा पुख्ता करने की भी जरूरत है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान पर

बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। आज कोई भी सब्जी 80 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति किलो से कम नहीं बिक रही है। टमाटर के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। बारिश के मौसम में सब्जियों की ढुलाई प्रभावित होने के कारण हर साल इसके दाम में बढ़ोतरी होती है। लेकिन मंडी में सब्जियों की आवक नहीं होने का हवाला देकर कुछ व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए भी दाम बढ़ा देते हैं। ऐसे में फूड इंस्पेक्टरों को मंडी पर कड़ी निगरानी के साथ सब्जियों के दाम पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ उपाय निकालने होंगे। अन्यथा भारी कीमत चुका कर सब्जी लेने से आम आदमी की जेब और जायका दोनों बिगड़ रहे हैं।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

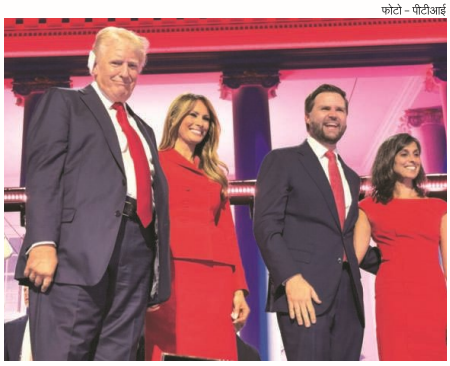

रिपब्लिकन पार्टी ने मिलवाउकी में गुरुवार को आयोजित अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरी बार अपना उम्मीदवार घोषित किया। ट्रंप ने नामांकन स्वीकार कर लिया। पेनसिल्वेनिया में शनिवार को ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया था और एक गोली उनके कान पर लगी थी।

दैनिक जागरण
लोभ मीठे विष के समान होता है

साइबर संकट

माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में खराबी से दुनिया भर में जो संकट पैदा हुआ, उससे सबक सीखने की आवश्यकता है। जब एक साफ्टवेयर कंपनी के सर्वर में खराबी से इतनी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तो इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि अन्य कंपनियों में एक साथ कोई खराबी आने या उनके साइबर हमले का शिकार होने पर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी से भारत समेत दुनिया के कई देशों में हवाई यातायात बाधित हुआ, बैंकों का कामकाज थमा, टीवी चैनलों का प्रसारण रुका, सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों के काम में खलल पड़ा और अमेरिका में तो आपातकालीन सेवाएं भी ठप पड़ गईं। फिलहाल इसका अनुमान लगाना कठिन है कि माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया को कितना अधिक नुकसान उठाने के साथ कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन यह ठीक नहीं कि तकनीक पर निर्भरता ऐसी विश्वव्यापी समस्या खड़ा कर दे। यह एक विडंबना ही है कि माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में खराबी तब आई, जब साइबर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे थे। इन उपायों ने ही साइबर सुरक्षा को संकट में डालने का काम किया। माइक्रोसाफ्ट ने कहा है कि खामी का पता लगा लिया गया है और शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि स्थितियां सामान्य होने में दो-तीन दिन का समय लग सकता है।

निश्चित रूप से आज के युग में तकनीक के बगैर किसी का काम चलने वाला नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में तकनीक का प्रवेश हो चुका है, लेकिन समस्या यह है कि इस तकनीक पर कुछ बड़ी टेक कंपनियों का वर्चस्व है। इस वर्चस्व का लाभ उठाकर ये कंपनियां कई बार मनमानी करती हैं। कभी-कभी तो वे अपनी सेवाएं लेने वालों पर मनचाही शर्तें थोपती हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग नियम बनाती हैं। निजी टेक कंपनियों के वर्चस्व और उनकी मनमानी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को एकजुट होना होगा। पता नहीं दुनिया के प्रमुख देश टेक कंपनियों के एकाधिकार का सामना करने और उनकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एकजुट हो पाएंगे या नहीं, लेकिन कम से कम भारत को तो इस दिशा में कदम उठाने ही चाहिए। ऐसा इसलिए और भी आवश्यक है, क्योंकि यह देखने में आ चुका है कि इन कंपनियों ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नियम-कानूनों का पालन करने से इन्कार कर दिया। इस मामले में सोशल नेटवर्क साइट्स चलाने वाली कंपनियों का रिकार्ड तो बहुत ही खराब है। यह सही समय है कि तकनीकी क्षेत्र के भारतीय कारोबारी अमेरिका आधारित बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार का सामना करने के लिए आगे आएं-ठीक वैसे ही, जैसे हाल में ओला कैब्स के भाविश अग्रवाल गूगल मैप्स के खिलाफ आए।

जिम्मेदारी का अहसास

बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर स्तर पर हरसंभव प्रयास कर रही है। इससे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति भी बढ़ी है। जाहिर है, जब सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, तो विभागीय अधिकारियों तथा शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। किंतु, इस संदर्भ में अभी भी जो परिस्थिति हो रही, वह बहुत ही चिंताजनक है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज कराने को पोर्टल बनाने के साथ-साथ नियंत्रण कक्ष तथा वाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। इन पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के समय पर स्कूल नहीं आने, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता खराब होने, वर्षा में स्कूल की छत से पानी टपकने, स्कूल में बिजली और बेंच आदि की दिक्कत होने जैसी शिकायतें मिल रही हैं। यहां तक कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक द्वारा पैसे मांगने की शिकायत भी की गई है। संभव है कि इनमें कुछ शिकायतें दुर्भावनापूर्ण हों। लेकिन, इससे साफ है कि सरकार की तमाम कोशिशों पर अधिकारियों एवं शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं होना भारी पड़ रहा है। अच्छी बात है कि इन शिकायतों के त्वरित निपटारे की कोशिश भी की जा रही है। स्थिति बता रही है कि मानीटरिंग की व्यवस्था और सख्त की जाए तथा किसी भी मामले में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

> जब तक व्यवस्था में शामिल लोग अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती

अमेरिका में बदल गया चुनावी माहौल

हर्ष वी. पंत

जहां ट्रंप निरंतर मजबूत हो रहे हैं, वहीं बाइडन लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं और उन पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बढ़ गया है

अवधेश राजपूत

रिपब्लिकन पार्टी कन्वेंशन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस के नाम पर भी मुहर लग दी गई। यूं तो इस पलान से पहले ही चुनाव में ट्रंप का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन बीते दिनों उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनकी जीत की संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ गई हैं। इस हमले के बाद ट्रंप के तेवर भी बदले हुए नजर आए। रिपब्लिकन कन्वेंशन में वह अपनी चिरपरिचित आक्रामक शैली के विपरीत कुछ विनम्र दिखे, जो यह दर्शाने का संकेत था कि वह समावेशी नीतियों संग सभी को साथ लेकर चलने वाले राष्ट्रपति बनने का प्रयास करेंगे। इस दांव से वह फ्लोटिंग या मध्यमार्गी मतदाताओं को भी साधते दिखे। रुख में इस बदलाव के बावजूद ट्रंप ने चीन से लेकर आव्रजन और इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दों पर अपना पारंपरिक कड़ा रुख भी दिखाया कि अहम नीतिगत मुद्दों पर उनका रवैया बदलने वाला नहीं।

जहां ट्रंप निरंतर मजबूत हो रहे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके प्रतिद्वंद्वी एवं मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। उन पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है और अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद बाइडन अपनी दावेदारी वापस ले लें। फिलहाल उनकी दावेदारी वापस लेने का प्रश्न तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मौजूदा हालात में उनकी हालत जरूर पतली है। यहां तक कि डेमोक्रेट्स के आंतरिक सर्वे में भी बाइडन 14 प्रमुख राज्यों में ट्रंप से पिछड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में इनमें से पांच राज्यों-एरिजोना, जार्जिया, मिशिगन, पेंसिलवेनिया और विस्कांसिन में बाइडन ने जीत हासिल की थी। डिबेट में लचर प्रदर्शन के बाद कोलोराडो, मिनिसोटा, न्यू मेक्सिको और न्यू हैंपशायर में भी उनकी स्थिति कमजोर पड़ी है।

अमेरिका में जो राजनीतिक परिदृश्य आकार ले रहा है, उसे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी बुरी तरह विभाजित नजर आ रही है। यह स्पष्ट दिख कि बाइडन किसी भी तरह ट्रंप को चुनौती देने में सक्षम नहीं। यही कारण है कि पार्टी के भीतर बाइडन पर अपनी दावेदारी वापस लेने की आवाजें उठ रही हैं। कैलिफोर्निया में पार्टी के वरिष्ठ नेता एहम शिफ ने तो खुलेआम कहा कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख देगा और मुझे इसकी चिंता सता रही है कि क्या राष्ट्रपति बाइडन नवंबर में होने वाले चुनाव में ट्रंप को हरा सकते हैं? हाल तक बाइडन यही संकेत देते आए हैं कि वह मुकाबले में बने रहेंगे, लेकिन इस शीर्ष पद के लिए वह अपनी ही पार्टी के लोगों को आश्वस्त करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर उन पर उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बढ़ता है तो इस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए।

डेमोक्रेट खेमे में कई अपने भी बाइडन से मुंह मोड़ रहे हैं, वहीं ट्रंप की पार्टी में कभी विरोधी रहे नेता भी उनके पीछे एकजुट हो गए। कुछ समय पहले तक रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप की दावेदारी के विरोधी निक्की हेली, रोन डीसैंटिस और मार्को रुबियो जैसे नेता अब एकस्वर में उनका समर्थन कर रहे हैं। गोलीबारी के बाद कान पर बंधी पट्टी के साथ अपनी लड़ाई को पुरजोर तरीके से जारी रखने का एलान करने वाली ट्रंप की तस्वीर को हाल के दौर के एक बेहद ताकतवर प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इस तस्वीर ने कैपिटल हिल पर हिंसा के आरोपों का सामना करने वाले नेता के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाने का काम किया।

दुविधाएं रिपब्लिकन खेमे में भी कुछ कम नहीं दिखतीं। अपने विरोधी रहे जेडी वेंस को ट्रंप ने उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया है। 2016 में वेंस ने यहां तक कहा था कि ट्रंप 'अमेरिका के हिटलर' साबित हो सकते हैं। उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं तो इस नाते वह धुर दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों के भी निशाने पर रहे हैं। 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' जैसे अभियान चलाने वाली पार्टी के लिए वेंस के परिवार की बहुसांस्कृतिक जड़ें आव्रजन विरोधी एजेंडे में फिट नहीं बैठतीं। यह न भूलें कि अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी तपिश दोनों प्रमुख दलों को झेलनी पड़ रही है। एक-दूसरे को दुश्मन की तरह देखने का सिलसिला उस स्तर तक पहुंच गया है कि ट्रंप पर हमले के बाद भी मेल-मिलाप के कोई प्रयास नहीं किए गए। रिपब्लिकन कन्वेंशन में भले ही एकता के भाव पर जोर दिया गया हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि पार्टी में ट्रंप से इतर रवैया रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं। ट्रंप के नजरिये का विरोध करना एक तरह से पार्टी को चुनौती देने जैसा बना दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने इस मामले में खुद को फिलहाल पार्टी संगठन से ऊपर स्थापित कर दिया है।

ट्रंप पर हुए हमले ने राजनीतिक परिदृश्य को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। इस हमले पर वेंस ने लिखा कि यह इकलौता मामला नहीं है और बाइडन खेमा किसी भी कीमत पर ट्रंप को रोकने पर आमादा है। यह बात और है कि अमेरिका के राजनीतिक माहौल की भड़काने में ट्रंप की भूमिका को उनके समर्थक फिलहाल अपनी सुविधा के हिसाब से अनदेखा कर रहे हैं। दूसरी ओर, बाइडन कोई प्रभावी बात कहने के बजाय केवल यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं कि कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। वह भले ही कह रहे हों कि राजनीतिक बहस रणभूमि या किसी की हत्या के प्रयास में तब्दील नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न यह है कि उनके कहे को कोई सुन भी रहा है या नहीं? ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए डेमोक्रेट्स के लिए हवा को अपने पक्ष में मोड़ना और मुश्किल हो सकता है।

नवंबर में अभी कुछ समय शेष है। राजनीति में कई बार एक दिन भी बहुत होता है। डेमोक्रेटिक पार्टी अभी भी खुद को नए सिरे से खड़ा करके ट्रंप को चुनौती दे सकती है। यहां तक कि बाइडन की जगह किसी और को प्रत्याशी बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं, मगर इससे इन्कार नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बीते कुछ दिन बाजी पलटने वाले साबित हो सकते हैं। इनोंने चुनाव की बुनियाद को बदलकर रख दिया है।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

कार्यशील आबादी के सदुपयोग की चुनौती

डा. सुरजीत सिंह

जनसांख्यिकीय लाभांश के दम पर भारत 2047 तक विकसित देश बनने का सपना साकार कर सकता है

समय की मांग है कौशल प्रशिक्षण। फाइल

विकसित देशों में कामकाजी युवाओं की घटती संख्या को देखते हुए भारत की 65 प्रतिशत से अधिक कार्यशील आबादी निश्चित रूप से जनसांख्यिकीय लाभांश है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 64 वर्ष के लोगों की संख्या 90 करोड़ है। भारत सरकार के अनुसार इस दशक के अंत तक भारत की कार्यशील जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी, जिससे अगले तीन दशकों में वैश्विक कार्यबल में भारत का योगदान 22 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, जो एशिया के संभावित कार्यबल के आधे से अधिक होगा। अगले तीन दशकों में भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश दोहन का स्वर्णिम अवसर रहेगा। जनसांख्यिकीय संरचना के उपयोग के लिए योजनाओं व कार्यक्रमों को युवा कार्यशक्ति के अनुसार लागू करने पर ही सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और लाभों को हासिल किया जा सकता है। भारत जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाने में सफल रहता है तो 2047 तक विकसित देश बन सकता है। भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर 2055-56 तक रहेगा।

बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती क्रय शक्ति ने आर्थिक विकास को गति दी है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग के बढ़ने से बाजार का आकार भी बढ़ रहा है। पिछले दशक में भारत के उपभोक्ता बाजार का आकार लगभग दोगुना होकर 2.1 लाख करोड़ डालर हो गया है। भारत दसवें सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार से आज दुनिया के चौथे सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में बदल गया है, जिसने विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए विकास के सुनहरे अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। उभरते भारत में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र ही हैं, जो तेजी से जनसांख्यिकीय लाभांश दिलवाने में सक्षम हैं। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर मजबूत होती आपूर्ति शृंखला ने भी विकास की संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में भारत के सस्ते श्रम का लाभ लेकर वैश्विक निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आकर्षित किया जाना चाहिए।

भारत के बढ़ते बाजार में निर्माण, सार्वजनिक सेवाएं, श्रम गहन विनिर्माण, व्यापार, परिवहन और पर्यटन, ई-कामर्स और शहरी केंद्रों में अन्य उपयोगिता सेवा केंद्र आदि तेजी से बढ़ते ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अतिरिक्त श्रम आपूर्ति को रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त किया जा सकता है। कपड़ा, खिलौने, जूते, आटोमोबाइल, खेल के सामान, कृषि प्रसंस्करण, रेस्तरां, होटल, खनन, स्वास्थ्य सेवा आदि ऐसे श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र हैं, जहां अकुशल और अर्ध-कुशल श्रम को आसानी से खपाया जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापार और लेनदेन की लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, जमीनी स्तर पर व्यापार करने में आसानी और श्रम कानूनों और कराधान प्रणाली को और तर्कसंगत बनाना होगा। श्रम शक्ति में होने वाली प्रत्येक वृद्धि सदैव अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाती है, परंतु यह इस पर निर्भर करता है कि जनसांख्यिकीय लाभांश लेने के लिए देश के संसाधनों और मानवीय बुनियादी ढांचे में निवेश की दर क्या है।

जनसांख्यिकीय लाभांश लेने के अधूरे प्रयास जटिल चुनौतियां भी खड़ी कर रहे हैं। तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, शहरीकरण का दबाव, वृद्ध लोगों की बढ़ती संख्या आदि अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं, जिसकी लागत समय के साथ और बढ़ेगी। जनसांख्यिकीय लाभांश लेने के लिए देश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को भी बढ़ाना होगा। जनसांख्यिकीय लाभांश की सबसे बड़ी बाधा देश के युवाओं की मानसिकता भी है। भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण युवाओं की मानसिकता ऐसी है कि वे केवल सरकारी नौकरी में ही भविष्य तलाशते हैं। सिविल सेवा, रेलवे, एसएससी आदि के सीमित पदों के लिए लाखों युवाओं की प्रतिभागिता बताती है कि देश की अधिकांश युवा आबादी के पास उचित कौशल न होने से उनके पास कोई उत्पादक काम नहीं है। दूसरा विरोधाभास यह है कि भारत में कुल कार्यबल के केवल तीन प्रतिशत लोग ही औपचारिक रूप से कुशल श्रमिक हैं। जबकि चीन में 24 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत, ब्रिटेन में 68 प्रतिशत और जापान में 80 प्रतिशत लोग कुशल श्रमिक हैं। बढ़ते कार्यबल और कुशल श्रमिकों की मांग की इस खाई को भरने के लिए नई शिक्षा नीति में भले ही एक पहल की गई है, परंतु इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि भारत के उच्चस्तरीय तकनीकी संस्थानों जैसे आइआइटी, आइआइएम और आइआइएसी में उद्योगों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

युवाओं को नौकरी की जड़ मानसिकता से निकाल कर अपना व्यवसाय करने की दिशा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए बैंकिंग, उद्योग और सरकार आदि पक्षों को एक मंच पर आकर युवाओं को प्रतिस्पर्धी बनाने, डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के द्वारा व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति भी जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लाभों को प्राप्त करने में मुश्किलें पैदा करती है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन परीक्षा

हम सबके भीतर ईश्वर का वास है। इस पंक्ति से एक स्वाभाविक जिज्ञासा जन्म लेती है कि यदि हमारे भीतर वास्तव में ईश्वरीय तत्व है तो हम बुरे कर्म क्यों करते हैं? या यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो ईश्वर रोकता क्यों नहीं? यदि आप विचार करें तो पाएंगे कि किसी भी प्रकार का बुरा कर्म अंतःकरण को आनंद नहीं देता। वह हमारी राक्षसी प्रवृत्ति को भले ही कुछ संतुष्ट कर दे, किंतु भीतर जो उसका अनुभव जाता है, वह अशांति एवं व्याकुलता ही उत्पन्न करता है।

ईश्वर बुरे कर्म करने से तत्काल ही रोकता है। जब भी मनुष्य बुरा कर्म करने को प्रवृत्त होता है, तत्क्षण उसके मन में संदेह, भय, लज्जा, तम से आच्छादित होने के भाव उत्पन्न होते हैं। अंतरात्मा की पुकार अक्सर ही मन को उद्वेलित करती है। बुरे कर्म करने के बाद ग्लानि का भाव भी अक्सर ही सिर उठाता है। क्या यह अपने भीतर ईश्वरीय तत्व के विद्यमान होने का पर्याप्त प्रमाण नहीं है? यदि ईश्वर चाहे तो संसार में पाप कर्म नहीं हो सकते, ऐसी भी जिज्ञासा हो सकती है। सत्य बात यह है कि ईश्वर किसी भी जीव की स्वतंत्रता नहीं छीनता। यदि ईश्वर जीवों की स्वतंत्रता छीन ले, उन्हें अपने एक यंत्र की तरह प्रयोग करे तो उनकी उन्नति नहीं हो सकती।

जिस प्रकार परीक्षा के समय शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तिका में सही-गलत उत्तर लिखते देखता है, किंतु उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उत्तर सही न होने पर उन्हें टोकता नहीं, उन्हें सही उत्तर भी नहीं बताता। उसे प्रकार जीवन में परीक्षा के ऐसे क्षण आते हैं, जहां हमारी तैयारी की जांच होती है, हमें सही उत्तर स्वयं ही खोजने होते हैं। 'हरि अनंत हरि कथा अनंता।' अनंत को समझने के लिए बुद्धि का विस्तार भी अनंत तक होना आवश्यक है। सीमित बुद्धि में बस इतना ही किया जा सकता है कि ईश्वर के किसी भी कृत्य के प्रति मन में संदेह न लाया जाए।

द्विवंकल तोमर सिंह

कई राज छिपाए है शनि का 'टाइटन'

प्रदीप

टाइटन की सतह पर सक्रिय नदीप्रणाली, जैसे नहरों, झीलों, सागरों आदि की उपस्थिति के ठोस साक्ष्य मिले हैं

शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद (उपग्रह) टाइटन के विचित्र नदी तंत्रों में लहरें, धाराएं, मुहाना और जलडमरूमध्य आदि शामिल हैं। साइंस जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक हालिया शोध पत्र में यह जानकारी दी गई है। शोध पत्र के लेखकों ने नासा के उस कैसिनी मिशन के अभिलेखीय डेटा का उपयोग किया है, जिसने 2004 और 2017 के दौरान शनि का अवलोकन किया था। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा टाइटन ही इकलौता ऐसा ज्ञात खगोलीय पिंड है, जिसकी सतह पर सक्रिय नदी प्रणाली, जैसे नहरों, झीलों, सागरों आदि की उपस्थिति के ठोस सक्ष्य मिले हैं। हालांकि यह पानी के रूप में नहीं हैं, बल्कि इथेन और मीथेन जैसे तरल हाइड्रोकार्बन हैं।

कैसिनी मिशन के दौरान ऐसे संकेत मिले थे कि टाइटन पर कुछ ऐसे कार्बनिक तत्व विद्यमान हैं, जिन्हें जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। इसका वायुमंडल भी काफी सघन है जो इसे हानिकारक अंतरिक्षीय किरणों (कास्मिक रेडिएशन) से सुरक्षा प्रदान करता है। कार्नेल विश्वविद्यालय के ग्रह विज्ञानी वैलेरियो पोगियली के मुताबिक, 'टाइटन वास्तव में पृथ्वी जैसा ही एक खगोलीय पिंड है, जिसमें घने नाइट्रोजन वातावरण में संचालित मीथेन आधारित हाइड्रोलाजिकल निकाय द्वारा आकार दिए गए बहुत ही परिचित सतही आकृति विज्ञान का एक विविध सेट है।'

सैद्धांतिक रूप से टाइटन पर वे सभी बुनियादी रसायनिक तत्व मौजूद हैं, जो जीवन निर्माण के लिए जरूरी हैं। इस बात की भी काफी संभावना है कि टाइटन पर जीवन विद्यमान हो, लेकिन निश्चित रूप से वह पृथ्वी के जीवन रूपों से अलग और नाइट्रोजन-मीथेन पर आधारित होगा। विज्ञानी यह दावा करते रहे हैं कि टाइटन की मौजूदा परिस्थितियां भविष्य में ईसानी बस्तियां बसाने के एकदम अनुकूल हैं। कई अध्ययनों के मुताबिक चूंकि टाइटन की मौजूदा विशेषताएं कुछ-कुछ शुरुआती पृथ्वी जैसी हैं, इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि टाइटन के समुद्रों में भी प्राचीन पृथ्वी की भांति जीवन के बीज फल-फूल रहे हों। कई अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आज से लगभग पांच अरब साल बाद, जब सूर्य के क्रोड (कोर) में मौजूद हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो जाएगा और वह ऊर्जा पैदा करने के लिए अन्य भारी तत्वों को जलाना शुरू कर देगा, तो वह एक लाल महादानव तारे में परिवर्तित हो जाएगा। इस परिवर्तन के दौरान सूर्य धीरे-धीरे बुध, शुक्र और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा, लेकिन तब टाइटन पर निवास योग्य परिस्थितियां (हैबिटेबल जोन) होंगी। टाइटन भविष्य में मानव का नया घर बन सकता है। टाइटन के बारे में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। (लेखक विज्ञान संचारक हैं)

मेलबाक्स

पूरक बनें संगठन और सरकार

'भाजपा में खींचतान' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में भाजपा की मौजूदा दशा-दिशा को रेखांकित किया गया है। यह सही है कि लगातार दो बार से केंद्र में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की रही, जहां एक बार पार्टी ने सपा-बसपा के गठजोड़ के बावजूद बाजी अपने नाम की, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसे लेकर पार्टी में आंतरिक स्तर पर मंथन बहुत स्वाभाविक है जो कि होना भी चाहिए, लेकिन इसके चलते आंतरिक कलह का सतह पर उभरना पार्टी की राह में कंटि बिछाने का ही काम करेगा। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाने से पार्टी की ही फजीहत होनी है और आने वाले उपचुनाव में भी उसका गलत संदेश जाएगा। ऐसे में भाजपा के लिए यही सही होगा कि पार्टी अपने संगठन और सरकार में संतुलन बनाकर अपनी नीतियों पर आगे बढ़े। वास्तव में संगठन और सरकार एक दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर पूरक बनें तभी बेहतर परिणाम सामने आते हैं।

केशव तिवारी, आजमगढ़

भारत-रूस संबंध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मास्को यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बड़े आत्मीयता के भाव से मिलना दोनों देशों की प्रगाढ़ होती मित्रता का द्योतक है। हालांकि यूक्रेन एवं अमेरिका ने भारत-रूस की बढ़ती नजदीकियों पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन कई कूटनीतिक अर्थों में भारत और रूस के बीच संबंधों का मजबूत होना दोनों देशों के व्यासायिक हितों को सधता है। रूस ऊर्जा के मामले में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता सहयोगी देश है। कृषि प्रधान भारत को रूस से एक-तिहाई उर्वरक मिलता है। मास्को यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन में चल रहे युद्ध की नये-तुले कूटनीतिक शब्दों में आलोचना करते हुए वैश्विक शांति की स्थापना की संभावनाओं पर भी बल दिया है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

छात्रों को हुनरमंद बनाया जाए

'रोजगार के साधन का समाधान' शीर्षक आलेख में संजय गुप्त ने सरकार को अच्छी सलाह दी है कि शिक्षा को कौशल विकास से जोड़कर छात्रों को हुनरमंद बनाया जाए ताकि वह जब शिक्षण संस्थानों से निकलें तो उन्हें रोजगार के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़े। यार रहे, आज हर क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं की ही मांग है। आज के छात्रों को कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में रोजगार योग्यता कौशल को परिभाषित करने, मापने और निर्माण करने के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अक्सर साफ्ट स्किल्स को कहे जाने वाले रोजगार कौशल व योग्यताएं, जो अकादमिक ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता से परे हैं। वे मूलभूत कौशल हैं, जो व्यक्तियों को कार्यस्थल में प्रभावी ढंग से संलग्न होने, बदलते वातावरण के अनुकूल होने और सहकर्मियों व ग्राहकों के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। रोजगार कौशल में संचार, टीम वर्क, समस्या-समाधान, नैतिकता, व्यवसायिकता और संसाधनों के प्रबंधन सहित कई तरह की क्षमताएं शामिल हैं। छात्रों के लिए शैक्षणिक ज्ञान और रोजगार कौशल-जैसे संचार, समस्या-समाधान और टीम वर्क का मिश्रण विकसित करना बहुत जरूरी है। ये कौशल आधुनिक कार्यबल के अनुकूल होने, लचीलापन बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि छात्र माध्यमिक शिक्षा के बाद की सफलता के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों। बेरोजगारी तब पैदा होती है, जब कामगारों के कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच कोई मेल नहीं होता। भारत में बहुत से लोगों को उनके कौशल के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती या आवश्यक कौशल की कमी के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिलती और शिक्षा का सार खराब होने के कारण उन्हें संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

हिन्दुस्तान 1936

साइबर संकट

एक दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने लगभग पूरी दुनिया को जिस तरह से प्रभावित किया है, वह न केवल दुखद, बल्कि चिंताजनक है। इसे एक आधुनिक आईटी संकट कहा जा सकता है, जिसने दुनिया भर में न सिर्फ साइबर आधारित कामकाज को प्रभावित किया, बल्कि बड़े पैमाने पर इससे परिवहन भी बाधित हुआ है। इस वजह से दुनिया को कितना नुकसान हुआ है, इसका हिसाब लगाने में अभी समय लगेगा। नुकसान का एक पहलू हवाई सेवा के नजरिये से देखा जा सकता है। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सिरियम के अनुसार, वैश्विक आईटी संकट या आउटेज के कारण 1,390 उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गईं। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में 512, जर्मनी में 92, भारत में 56, इटली में 45 और कनाडा में 21 उड़ानें रद्द कर दी गईं। टिकट लेने से रद्द कराने और रिफंड लेने तक यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। अमेरिका समेत कई देशों में तो रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। यह संकट इतना व्यापक है कि स्थिति के सामान्य होने में अभी कुछ समय लग सकता है।

आखिर ऐसा क्यों हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि वह मध्य अमेरिकी क्षेत्र में अपनी सेवाओं की जांच कर रहा है, जिनकी वजह से दुनिया भर में अनेक प्रकार की सेवाएं बाधित हुई हैं। इस संकट से सर्वाधिक प्रभावित देशों में ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, तो इस पर्यटन को पहचान चाहिए, हर देश को अपने-अपने स्तर पर अपने नुकसान का सही आकलन करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से ही शायद सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के काम न करने की शिकायतें सामने आईं। वहां बैंक, एयरलाइन्स, मीडिया प्रसारण तक रुक गया। कई संस्थान ऑफलाइन काम करने को मजबूर हो गए। अभी तक की सूचनाएं यही इशारा करती हैं कि माइक्रोसॉफ्ट संबंधी इस संकट के पीछे एक साइबर सुरक्षा फर्म क्राउडस्ट्राइक का हाथ है। कोई ऐसा अपडेट किया जा रहा था, जो बुनियादी रूप से वैश्विक साइबर तंत्र के अनुरूप नहीं था। यह कोई साइबर हमला नहीं था, बल्कि सेवा में कुछ अपडेट करने के चक्कर में यह महासंकट खड़ा हो गया। जिम्मेदार कंपनियां इस संकट के लिए तैयार नहीं थीं, तो जाहिर है, साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउडस्ट्राइक के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट को भी आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। विकसित देशों में अनेक कंपनियां इस संकट की भरपाई या मुआवजा मांगेंगी। वाकई, यह एक ऐसा संकट है, जिसे उदारता बरतते हुए भुला देना आने वाले समय के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। यदि इरादतन कोई अपराध नहीं हुआ है, तब भी जो लापरवाही या उदासीनता बरती गई है, उसका माकूल हिसाब होना चाहिए।

अगर इरादतन कोई अपराध नहीं हुआ हो, तब भी जो लापरवाही या उदासीनता बरती गई है, उसका माकूल हिसाब होना चाहिए। भविष्य के लिहाज से यह जरूरी है।

हालांकि, इसमें कोई दोराय नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट अपने पैमाने पर सक्रिय होगी और फिर ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, पर यह दुनिया की तमाम सरकारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जागने व तैयार होने का समय है। ध्यान रहे, ऐसे संकट से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपनी साजिश में ऐसी कमियों का लाभ उठाने का दुस्साहस कर सकते हैं। अभी तक डार्क वेब दुनिया में यह बात पता चल चुकी होगी कि इस संकट को कैसे अंजाम दिया गया और अर्थव्यवस्था या सेवा का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अतः साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई है। सरकारों को भी नए सिरे से प्रबंध करना चाहिए, ताकि बड़ी आईटी कंपनियां अपने आर्थिक लाभ के लिए साइबर सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न करने पाएं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 20 जुलाई, 1949

राजस्थान का गतिरोध

राजस्थान की राजनीति में पिछले दिनों एक खेदजनक गतिरोध उत्पन्न हो गया था। राजस्थान में जो अन्तरिम मंत्रिमण्डल पं. हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में बना, उसमें और राजस्थान की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में शुरू से ही रस्साकशी शुरू हो गई। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सामने मंत्रिमण्डल के विरुद्ध और कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। मंत्रियों को त्यागपत्र देने की हिदायत दी गई और उसका पालन न करने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करने की धमकी दी गई। राजस्थान के कांग्रेसजनों के इस आपसी विवाद ने प्रान्त के राजनीतिक वातावरण को क्षुब्ध बना दिया था और कांग्रेस की प्रतिष्ठा और प्रभाव को हानि पहुंच रही थी। राजस्थान की बड़ी-छोटी रियासतों के एकीकरण के बाद नये शासन के सामने अनेक पेचीदा समस्याएं उपस्थित हुईं। राजस्थान के कांग्रेस संगठन ने यदि संयुक्त होकर इन समस्याओं को हल करने में सहयोग दिया होता तो कितना अच्छा होता। किन्तु दुर्भाग्यवश यह नहीं हुआ।

यदि इस बीच कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक न हुई होती तो राजस्थान का मामला और तूल पकड़ सकता था। कार्यसमिति ने इस विवाद का आखिरी निपटारा कर दिया है। उसने निर्णय दिया है कि राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को अन्तरिम मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का कोई अधिकार नहीं था, कारण एक समझौते द्वारा यह मान लिया गया था कि अन्तरिम मंत्रिमण्डल रियासती सचिवालय के प्रति उत्तरदायी होगा। कांग्रेस कार्यसमिति ने राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अपने पूर्व अध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने की कार्रवाई को भी नापसन्द किया है। कार्यसमिति कांग्रेस की सर्वोच्च कार्यकारिणी संस्था है, इसलिए उसका फैसला अन्तिम होता है। राजस्थान के विवाद ने जितना उग्र रूप धारण कर लिया था, उसको देखते हुए उसका यह फैसला राजस्थान के कतिपय कांग्रेसजनों को असन्तोषकारक प्रतीत हो सकता है, किन्तु अनुशासन के नाते राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और प्रान्त के प्रत्येक कांग्रेसजन को इस निर्णय के आगे सिर झुकाना चाहिए।

जब अठारहवीं लोकसभा अपने पहले आम बजट के लिए तैयार है, तब देश की पहली लोकसभा में पेश पहले आम बजट की चर्चा प्रासंगिक है। तब बजट के कई विषय और उस पर विचार बिल्कुल अलग थे, पर कुछ मुद्दे ऐसे भी थे, जिन पर आज भी बहस की गुंजाइश और जरूरत है।

आर्थिक संकटों से परे जाकर बनाया बजट

यहां स्कैन करें

ए के गोपालन | वामपंथी नेता व सांसद

- देश में अकाल फैल रहा है और कारखानों से लोग निकाले जा रहे हैं।
- कागज, चमड़ा, सोडा, सीमेंट, कांच आदि का भी उत्पादन कम हो गया है।
- बजट में गंभीर आर्थिक संकट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

बजट को सच्चा और साहसपूर्ण कहा गया है। ठीक है, थोड़े से लोगों के हितों की रक्षा और देश के बहुसंख्यकों की उपेक्षा करने में यह साहसपूर्ण ही है। सरकार की वही पुरानी नीति और सिद्धांत इसमें भी हैं। ...सारे देश में अकाल फैल रहा है और कारखानों से लोग निकाले जा रहे हैं, तब यह कहना कि खाद्य सहायता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, साहसपूर्ण ही है। फिर कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना सन 1939 के स्तर पर पहुंचा देगी। अभी भोजन और नौकरी मांगने पर हम नहीं दे सकेंगे। इस विषय में गोरवाला समिति ने प्रतिवेदन में लिखा है : 'न केवल भारत सरकार अपितु कोई भी सरकार इस आधार पर नहीं चल सकेगी कि बहुत से काम शुरू करना थोड़े काम पूरे करने से अच्छा है। बुनियादी चीजें रोटी, कपड़ा व मकान है, आर्थिक बुराइयों को दूर कर तत्काल नया आर्थिक ढांचा बनाना होगा... । सरकार को बहुत से काम करने होते हैं, पर बुनियादी चीजें नहीं भूलनी चाहिए...।'

यह सरकार का मूल कर्त्तव्य है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो सरकार लोगों को रोटी नहीं दे सकती...(व्यवधान)। हमें एक-दूसरे की देशभक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। हम कांग्रेस के किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते। हम सरकार की नीति की आलोचना करते हैं। मैं कह रहा था कि जो सरकार लोगों को भोजन न दे सके, उसे वहां बैठने का अधिकार नहीं है। ... चाहे वह साम्यवादी सरकार हो या कांग्रेस सरकार या मिली-जुली सरकार, सभी पर यही बात लागू होती है।

यदि देश के अर्थ संकट को देखकर बजट बनाया गया होता, तो वह ऐसा नहीं होता। यदि कभी युद्ध हो, तो हमें निस्संदेह देश और उसके हितों की रक्षा करनी होगी। तब देश की रक्षा विषयक जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट बनाना होगा, पर जब चारों ओर भुखमरी है और पशु मर रहे हैं, तो तत्काल सहायता दी जानी चाहिए। हम योजनाओं के विरोधी नहीं हैं और उनके देश के हित में होने के कारण हम निश्चय ही उनका समर्थन करेंगे। पर योजना या बजट के आंकड़े कुछ भी हों, जहां तक रक्षा व्यय का संबंध है, धन और पदार्थ या मशीनें नहीं, बल्कि जनता का सहयोग हमारा आधार है। ...देखना यह है कि क्या इस बजट को जनता का विश्वास प्राप्त है?...

नए कर नहीं लगाए गए हैं, पर खाद्य सहायता न देना क्या गरीबों पर कर लगाना नहीं है? ...मंत्री जी कहते हैं कि यह मंदी लोगों के लिए वरदान सदृश आई है, पर क्लर्क, मजदूर, किसान और साधारण आदमी का 90 प्रतिशत व्यय तो खाद्यान्नों पर होता है और दूसरी चीजें वह खरीद ही नहीं पाता है। उल्टे मैं देखता हूं कि कई प्रदेशों में चमड़ा, वस्त्र और विशेषतः करघा आदि उद्योगों में बेकारी बढ़ रही है। मालाबार में अकेले त्रावनकोर-कोचीन में 5,58,000 लोग बेकार हो गए हैं। ...इसी प्रकार सामजिक, कागज, चमड़ा, सोडा, सीमेंट, कांच आदि का भी उत्पादन कम हो गया है।

आमने-सामने

उधर, हथकरघा आदि उद्योगों में बेकारी फैल रही है। मालावार के कारखाने बंद होने जा रहे हैं।...

फिर निर्माण कार्यों और सामाजिक सेवाओं तथा विशेष रूप से शिक्षा के लिए बहुत थोड़ी राशि दी गई है। ...शिक्षा के लिए कुल एक प्रतिशत दिया गया है। बजट में गंभीर आर्थिक संकट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ...देश में 89 प्रतिशत व्यक्ति खेतिहर मजदूर किसान हैं। जब तक उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती और औद्योगिकीकरण नहीं होता, हमें बाहरी बाजारों का मुख देखना होगा। ...भले हम 50 प्रतिशत धन सेना पर व्यय करें, पर सारे देश को संतुष्ट रहना चाहिए, सबको नौकरी, जमीन या काम मिलना चाहिए, अन्यथा अकेली सेना कुछ नहीं कर सकेगी। मेरा सुझाव है कि बजट में से एक तिहाई सेना पर, एक तिहाई सामजिक सेवाओं पर और एक तिहाई देश के विकास पर व्यय होना चाहिए। ...अभी यह बजट देश के करोड़ों लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करता है और निश्चय ही देश के लिए निराशाप्रद है।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

अपने देश की स्थिति उतनी बुरी भी नहीं

यहां स्कैन करें

टी टी कृष्णमाचारी | तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री

- माननीय मित्र ने यह कैसे समझ लिया कि स्थिति इतनी खराब है?
- कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जो सरकार के काबू के बाहर हैं।
- विश्वास दिलाता हूं कि इन सब बातों में हमारी दिलचस्पी कुछ कम नहीं है।

वाद-विवाद में कुछ माननीय सदस्यों ने आयव्ययक के सुझावों की आधारभूत धारणाओं को गलत बतलाया है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कीमतों के रुख तथा उत्पादन के रुख की ओर निर्देश किया है। इन धारणाओं की आलोचना विशेष रूप से श्री गोपालन ने की है। श्री गोपालन ने कुछ आंकड़े देकर यह कहा है कि यह धारणा कि उत्पादन की मात्रा कोई खास असंतोषजनक नहीं रही है, गलत है।

श्री गोपालन ने कहा कि वित्त मंत्री का यह कहना था कि कीमतों की वर्तमान मंदी तो लोगों के लिए एक अच्छी बात है। तो हम निस्संदेह यह मानते हैं कि आजकल कीमतें बहुत ऊंची हैं, यदि उनके नीचे गिरने की कोई संभावना होती, तो यह अच्छा ही था, पर यह तो नहीं कहा गया है कि कीमतों में कमी होने के फलस्वरूप उत्पादन में भी कमी आ गई है।

श्री गोपालन ने कहा कि कोयला, सीमेंट, ऊन की बनी चीजों, चीनी, सिगरेट, कागज, चमड़ा, कपड़ा गंधक का तेजाब, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, कांच की चादरों आदि का उत्पादन जनवरी 1952 में जनवरी 1951 की अपेक्षा कम रहा है। उन्होंने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आंकड़े दिए थे। अब मैं कुछ आंकड़े दूंगा, जिनसे यह मालूम होगा कि स्थिति वास्तव में इतनी बुरी नहीं है, जितनी मेरे माननीय मित्र ने बतलाई है।

जनवरी से मार्च तक का कोयले का उत्पादन इस वर्ष औसतन 31 लाख टन प्रति मास रहा है, जबकि जनवरी-मार्च 1951 में यह 28 लाख 50 हजार टन था। ...जनवरी 1951 में 33 करोड़ 89 लाख गज कपड़ा तैयार हुआ था, जनवरी 1952 में कपड़े का उत्पादन बढ़कर 34 करोड़ 46 लाख गज हो गया। ...सिगरेटों का उत्पादन...में अप्रैल में थोड़ी कमी हुई है। गंधक के तेजाब का उत्पादन... थोड़ा कम हुआ है। कास्टिक सोडा के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सोडा ऐश के उत्पादन में कुछ कमी हुई है, तो एक दो उद्योगों को छोड़कर शेष सब उद्योगों की सामान्य स्थिति ऐसी है, जिससे मेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री द्वारा बतलाई गई बातों की पुष्टि होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री गोपालन ने यह कैसे समझ लिया कि स्थिति इतनी खराब है।

जूट के उत्पादन में कुछ कमी जरूर हुई है, जिसका कारण संसार की बहुत सी परिस्थितियां हैं, परंतु इसकी स्थिति भी अब सुधरती जा रही है। ...त्रावनकोर से किए जाने वाले निर्यात के बारे में तीन मुख्य प्रश्न उठते हैं - नारियल की जटा तथा जटा से बनने वाली वस्तुओं का प्रश्न, काली मिर्च का प्रश्न तथा खोपरा की कीमतों का प्रश्न। ...हमें अपने लिए खाद्य तथा बड़ी मशीनें आदि मंगानी पड़ती हैं। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जो सरकार के काबू के बाहर हैं। ...मांग की अस्थिरता के बारे में सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती, फिर भी सरकार स्थिति की गंभीरता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। नारियल की जटा की निकासी स्पष्टतः कम हो गई है और उसकी गुणवत्ता के बारे भी कतिपय शिकायतें मिली हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इन सब बातों में हमारी दिलचस्पी कुछ कम नहीं है। ...हम कच्चे चमड़े का निर्यात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने चमड़ा उद्योग के लिए बाहर से कच्चा चमड़ा मंगवा रहे हैं।...

इसके अतिरिक्त जिन मामलों की चर्चा की गई है, वह है आयात-निर्यात्रण, विदेशी विनियोग आदि। इनके बारे में मैं तब कुछ कहूंगा, जब मेरे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। अब मैं सिर्फ छोटे उद्योगों के बारे में कुछ कहूंगा। करघा उद्योग, कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रति उपेक्षा दिखलाने की शिकायतें की गई हैं। करघा उद्योग का प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार उस पर विचार कर रही है। छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रश्न पर योजना मंत्री विचार कर रहे हैं और इस संबंध में शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय किया जाएगा।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

एक सर्वर की खराबी और दुनिया भर में हाहाकार

यहां स्कैन करें

मुकेश चौधरी | साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ

सवाल है कि आपात स्थिति के लिए तय 'बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान' (बीसीपी) पर कितना ध्यान दिया गया? यह सवाल माइक्रोसॉफ्ट के साथ-साथ उन कंपनियों से भी जुड़ा है, जो इसकी सेवाएं ले रही हैं।

शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी से पूरी दुनिया हलकान रही। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था खासा प्रभावित हुई और विमान सेवाओं, बैंकिंग सिस्टम व शेयर बाजार पर इसका काफी असर पड़ा। कई कंपनियों में काम-काज पूरी तरह से ठप हो गए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई यह समस्या क्राउडस्ट्राइक की वजह से आई, जो इससे जुड़ी एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। शुरुआती आशंका यही थी कि यह कोई साइबर हमला है, मगर बाद में साफ हो गया कि यह तकनीकी गड़बड़ियों का नतीजा है। दरअसल, क्राउडस्ट्राइक ने एक अपडेटकिया, जिसके बाद से ही दुनिया में जहां-तहां माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सपोर्ट वाले अधिकतर उपकरण बैठने लगे।

सवाल है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या माइक्रोसॉफ्ट की सेवा लेने वाली कंपनियां ऐसे हालात के लिए तैयार नहीं थीं? अगर थीं, तो उस तैयारी को अमल में लाने में इतना वक्त कैसे लगा? इस पूरे घटनाक्रम को कई पहलुओं से देखना होगा। निस्संदेह, ऐसा किसी कंपनी के साथ हो सकता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी की दुनिया में तकनीकी चूक की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मगर चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक भरोसेमंद वैश्विक ऑपरेटिंग सिस्टम है और अनगिन कंपनियां उस पर निर्भर हैं, इसलिए इस पूरे मामले में उसकी जिम्मेदारी कहीं अधिक बन जाती है। बड़ी-बड़ी कंपनियों का अपने साथ छोटी-छोटी दूसरी कंपनियों को रखना आम बात है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही किया और क्राउडस्ट्राइक को अपने साथ जोड़ा। सवाल यह है कि आपात स्थिति या आपदा जैसे हालात में मुश्किलें पैदा होने पर 'बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान' (बीसीपी) पर कितना ध्यान दिया गया? यह सवाल माइक्रोसॉफ्ट से भी उतना ही जुड़ा है, जितना उन कंपनियों से, जो इसकी सेवाएं ले रही हैं। बीसीपी असल में एक 'बैकअप प्लान' होता है, जिसमें प्रतिकूल हालात में भी कंपनी की सेवा बहाल रखने के जरूरी दिशा-निर्देश होते हैं। कंपनियां यह योजना तैयार रखती हैं, ताकि उनके काम पर असर न पड़े। माइक्रोसॉफ्ट के पास भी योजना होगी ही। मगर जब तक अपनी क्लाइंट कंपनियों की वह मदद कर पाती, तब तक देर हो चुकी थी।

स्पष्ट है, बीसीपी न सिर्फ मूल कंपनी को, बल्कि उसकी तमाम ग्राहक कंपनियों को भी पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, ग्राहक कंपनियों के पास इस बाबत सारी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, उनके इंजीनियरों को पता होना चाहिए और उनके सभी हितधारकों तक उस प्लान की पहुंच होनी चाहिए। साफ है, शुक्रवार को इन सबमें कहीं न कहीं चूक जरूर हुई। ऐसे में, माइक्रोसॉफ्ट यह जरूर पड़ताल कर रही होगी कि वह रिस्पॉन्स टाइम (किसी समस्या पर प्रतिक्रिया देने का समय) कितना कम कर सकती है? वैसे, यह किसी ख्यात कंपनी के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना स्टार्ट-अप के लिए। हां, छोटी कंपनियां बीसीपी नहीं रखतीं, क्योंकि इसके लिए अलग टीम की जरूरत पड़ती है और उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है।

इस मामले में यह देखना होगा कि अब ग्राहक कंपनियां किस तरह अपने घाटे को पाटती हैं? क्या माइक्रोसॉफ्ट मुआवजा देगी? अगर नहीं, तो क्या ग्राहक कंपनियां उसे अदालत में घसीट सकती हैं? क्या ऐसा करने का अधिकार उनके पास है? बेशक, यह सीधे-सीधे माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्राउडस्ट्राइक जिम्मेदार है, लेकिन क्या जो अपडेट वह कर रहा था, उसको जांचने का काम सिर्फ क्राउडस्ट्राइक का था या फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे।

बहरहाल, शुक्रवार जैसी घटना शायद ही पहले कभी हुई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पहले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अधिक नहीं थे। पहले सर्वर डाउन जैसी गड़बड़ियां ज्यादा होती थीं। हालांकि, अब इसमें काफी कमी आ गई है, क्योंकि इनको तुरंत संभाल लिया जाता है। फिर भी, कभी-कभी सर्वर डाउन की खबरें हम सुनते ही हैं, जैसा कि पिछले दिनों मेटा (फेसबुक) के साथ हुआ था। कुल मिलाकर, मुश्किल वक्त में कंपनियों का आपसी संचार काफी अहम होता है। ग्राहक कंपनियों को यह पहले से पता होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में हालात कैसे संभालने हैं? रिस्पॉन्स टाइम की जानकारी उनको होनी ही चाहिए। साथ ही, उस माध्यम की भी, जिसके द्वारा उनकी मुश्किलों को मूल कंपनी ठीक करेगी। तभी शुक्रवार जैसे हालात को हम बेअसर कर सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

कुदरत के रहस्य

नर और मादा बंदर एक पेड़ की शाखा पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। एक बिंदु आया, जब बंदरिया ने पूछा, 'जब सूर्य क्षितिज पर पहुंचता है, तो आकाश का रंग क्यों बदल जाता है?'

बंदर ने उत्तर दिया, 'अगर हमने सब कुछ समझाने की कोशिश की, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बस चुपचाप बैठें और इस रोमांटिक सूर्यास्त को अपने दिलों को खुशी से भरने दें।'

बंदरिया क्रोधित हो गई, 'तुम बहुत रूढ़िवादी और अंधविश्वासी हो। अब तुम्हारी तार्किकता में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस तुम जीवन का आनंद लेना चाहते हो।'

उसी समय, एक कनखजूरा उधर से गुजर रहा था। बंदर ने उससे पूछा, 'तुम अपने सभी पैरों को इतने सही तालमेल से कैसे हिला पाते हो?' जवाब आया, 'मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा।' बंदर ने कहा, 'सोचो! मेरी पत्नी जानना चाहती है।'

कनखजूरे ने अपने पैरों को देखा और कहना शुरू किया : 'ठीक है... पहले मैं मांसपेशी को हिलाऊंगा, नहीं... नहीं पहले मांसपेशी नहीं हिलाऊंगा, पहले मुझे अपने शरीर को इस दिशा में झुकाना होगा...' यह समझाने की कोशिश में उसने आधा घंटा लगा दिया कि वह कैसे अपने पैरों को हिलाता है और जितना अधिक प्रयास करता, उतना ही अधिक भ्रमित होता गया। वह वहां से आगे बढ़ना चाहा, तो पाया कि अब आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा। हताशा में कनखजूरा बंदर पर चिल्ला उठा, 'देखो, तुमने क्या किया? तुम्हें समझाने की उत्सुकता में मैं अब आगे बढ़ना भूल गया हूं।' बंदर ने सूर्यास्त का आनंद उठाते हुए बंदरिया से बोला, 'देखा तुमने? जब कोई सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है?'

पाउलो कोएल्हो

अमित शाह | केंद्रीय गृह मंत्री

हम भारत में एक ग्राम भी ड्रग्स न कहीं से आने देंगे और न ही देश की सीमाओं का ड्रग्स-व्यापार के लिए किसी प्रकार से इस्तेमाल होने देंगे। सभी एजेंसियों का लक्ष्य इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का होना चाहिए।

कांवड़ियों को सच पता होना चाहिए

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कावड़-यात्रा-मार्ग पर स्थित ढाबों, दुकानों या खाने-पीने वाले ठेलों पर मालिक का नाम प्रदर्शित करने संबंधी निर्देश पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जबकि ऐसे किसी निर्देश में कोई बुराई नहीं है। नाम प्रदर्शित होने से कांवड़ियों को किसी दुकान में खाना खाने में संकोच नहीं होगा। उनके मन में यह शंका नहीं होगी कि उनको जो खाना परोसा जा रहा है, वह किस तरह पका होगा। कांवड़िए चूंकि लहसुन, प्याज जैसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहते, इसलिए वे भी उन दुकानों में ही खाना खा सकेंगे, जो शुद्ध शाकाहारी होंगे। मूलतः शुचिता का ख्याल इस आदेश में रखा गया है, क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्य में पवित्रता का काफी महत्व होता है। कई बार लोग जाने-अनजाने भ्रमित होकर ऐसी दुकानों पर चले जाते हैं, जहां वे समझ-बूझकर शायद ही जाना चाहेंगे। खाना खाने के बाद यदि उनको सच्चाई पता चलती है, तो उन्हें काफी दुख होता है। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। वे पहले से जान सकेंगे कि उन्हें किस दुकान या ठेले से खाना खाना है और किस दुकान से नहीं। लिहाजा, विपक्षी दलों को इस पर सियासत करने से बचना चाहिए। हर बात पर राजनीति करना उचित नहीं। विरोध के लिए भी विरोध करना सही नहीं माना जाएगा। वास्तव में, यह सियासत का मसला है ही नहीं। यह तो विशुद्ध धर्म से जुड़ा मामला है, जिसमें शुचिता और पवित्रता काफी अहम मानी जाती है। इस निर्देश के बाद कांवड़िए स्वेच्छापूर्वक खान-पान कर सकेंगे।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

पसंद का ख्याल

कांवड़-यात्रा के मार्ग में फल-फूल रही दुकानों पर मालिकों का नाम स्पष्ट करने संबंधी निर्देश को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। असंख्य लोग इस फैसले के पक्ष में हैं, तो कई इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि लोगों के साथ लगातार हो रहे विश्वासघात की शिकायतों का संज्ञान लेकर ही यह कदम उठाया गया है। इस पर राजनीति कतई उचित नहीं। हम जानते हैं कि कैसे बीते वर्षों में फर्जी नाम से होटल आदि चलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। भेद खुलने पर रटा-रटाया बहाना दिया जाता है कि जिससे दुकान खरीदी, उसी के नाम पर चला रहे हैं। इससे लोगों के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को सच जानने का पूरा हक है और उन्हें यह अधिकार मिलना ही चाहिए। ऐसे में, यदि नाम प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं जान पड़ता।

मनोज पुरुषार्थी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

कांवड़ यात्रा

सामाजिक विभेद बढ़ाने वाला निर्देश

सत्तारूढ़ दल अपने जिन मुद्दों और विचारधारा को पहले छिप-छिपाकर लोगों के सामने रखता था, अब लोकसभा चुनाव में आशातीत सफलता नहीं मिलने के कारण उन मुद्दों पर खुलकर आगे बढ़ता दिख रहा है। लगता है, उसने अब आर या पार का फैसला कर लिया है। कम से कम कांवड़-यात्रा के मार्ग की दुकानों पर दिए गए निर्देशों से यही लगता है। क्या दुकानों, ठेलों या होटलों के मालिकों का नाम जाहिर करने का जारी फरमान संविधान की भावना के अनुरूप है? देश का संविधान भेदभाव खत्म करने की वकालत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, जाति, लिंग या अन्य किसी वजह से नागरिकों में कोई विभेद न हो। मगर इस पर गौर नहीं किया गया और यह निर्देश जारी कर दिया गया कि खाने-पीने के काम से जुड़े दुकानदार अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखेंगे। अब होगा यह कि धर्मविशेष के लोगों की दुकानों की लोग अनदेखी करने लगेंगे और उनकी दुकानों से खरीदारी बंद कर देंगे। इससे उनके कारोबार को घाटा होगा, जबकि त्योहारी मौसम में सभी दुकानदार मुनाफे की उम्मीद लगाए रखते हैं। जाहिर है, जब एक धर्मविशेष के दुकानदारों को घाटा होगा, तो वे दुखी होंगे, जिससे हमारी सामाजिक समरसता पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे सामाजिक विभेद और बढ़ सकता है और लोग धार्मिक भेदभाव अधिक करने लगेंगे। ऐसे में, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उचित ही कहा है कि शीर्ष अदालत को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उसे इसके पीछे की असल मंशा पता करनी चाहिए और इस निर्देश को तत्काल वापस लेने का आदेश देना चाहिए। जाने-माने पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने भी इस निर्देश की तुलना 'नाजी जर्मनी' से की है। सवाल है, क्या हम सचमुच में सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं? क्या सच में हमारा कामकाज संविधान के तहत चल रहा है? अगर नहीं, तो हमें यह तस्वीर बदलनी चाहिए।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

समाज को नुकसान

सावन का महीना भोलेनाथ के नाम होता है और बाबा भोलेनाथ सब पर दयालु रहते हैं। जो कोई भी उनको सच्चे मन से भजता है, वह इस भवसागर से पार हो जाता है। वह अपने भक्तों को धर्म या जातियों में नहीं बांटते, लेकिन हम इंसान जरूर एक-दूसरे से भेदभाव करते हैं। शायद इसीलिए कांवड़-यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के लिए नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है, हालांकि निर्देश में कहा गया है कि दुकानदार स्वेच्छा से ऐसा करेंगे, यानी उनके साथ कोई जबर्दस्ती नहीं है। फिर भी, इस निर्देश को वापस लेना चाहिए।

सौम्य, टिप्पणीकार

कल्पमेधा

विजय हमारे साथ में नहीं होती, लेकिन साहस और प्रयास से वह अक्सर मिल जाती है। मगर जो कायर हैं और नतीजों से डरते हैं, उन्हें नसीब नहीं होती।

- जवाहरलाल नेहरू

असुविधा की तकनीकत

कनीकी संसाधनों पर निर्भरता बढ़ते जाने से व्यवसाय-वाणिज्य, निजी और दफ्तरी कामकाज में तेजी तो आई है, मगर इसमें एक खराबी किस कदर दुनिया की सारी रफ्तार रोक देती है, इसका ताजा उदाहरण माइक्रोसाफ्ट के नए साफ्टवेयर में आई गड़बड़ी है। माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी आने से दुनिया भर के दफ्तरों में कामकाज लगभग ठप्प हो गया, रफ्तार थम गई। विभिन्न देशों में चौदह सौ से ऊपर हवाई सेवाएं रद्द करनी पड़ीं और हजारों हवाई जहाज देरी से उड़ पाए। टेलीविजन प्रसारण, बैंक सेवाओं, शेयर बाजार के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुए। हालांकि माइक्रोसाफ्ट के इंजीनियर इस गड़बड़ी को सुधारने में जुट गए, मगर इतने भर से दुनिया भर में अरबों रुपए का कारोबार प्रभावित हो गया। दरअसल, माइक्रोसाफ्ट ने एक नया साफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे उपभोक्ताओं को तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित सेवा देने का दावा किया गया था। यह साफ्टवेयर क्लाउड सेवा से जुड़ा हुआ है। उसमें क्राउड स्ट्राइक नामक साइबर सेंधमारी से सुरक्षा प्रदान करने वाले 'एंटीवायरस' को अद्यतन किया गया, तभी से गड़बड़ी शुरू हो गई। कंप्यूटर अपने आप बंद और चालू होने लगे। इससे माइक्रोसाफ्ट कंपनी की साख पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

हालांकि कुछ महीने पहले एलन मस्क ने भी माइक्रोसाफ्ट के 'एज' नामक नए साफ्टवेयर की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि यह साफ्टवेयर अव्यावहारिक है, जो कई कंप्यूटरों से एक साथ जुड़ जाता है और इस तरह इसकी सुरक्षा विश्वसनीय नहीं रह जाती। मगर तब माइक्रोसाफ्ट की तरफ से जवाब में कहा गया था कि यह साफ्टवेयर उपभोक्ता को कहीं भी बैठ कर आसानी से काम करने की सुविधा देता है। इसमें सेंधमारी का खतरा नहीं रहता। अब फिर से इस साफ्टवेयर की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। फिलहाल यह दावा करना मुश्किल है कि किसी साइबर अपराधी ने ऐसी गड़बड़ी पैदा की, पर ऐसी हरकत से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे-जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर लोगों की निर्भरता बढ़ती गई है, वैसे-वैसे इसके खतरे भी बढ़ते गए हैं। साइबर सेंधमार लोगों के बैंक खातों, दफ्तरों के दस्तावेजों, कंपनियों के लेखा-जोखा वगैरह में सेंधमारी करने लगे हैं। हर इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माता कंपनी साइबर सेंधमारी रोकने के लिए वायरसरोधी उपाय करती है। जो कंपनी इसमें पिछड़ जाती है, वह बाजार में भी पिछड़ जाती है। माइक्रोसाफ्ट ने भी इसी समस्या से बचाने के लिए नई तकनीक ईजाद करने का दावा किया था।

हर नई तकनीक में प्रायोगिक स्तर पर कुछ न कुछ अड़चन आती है। मगर जब कोई भरोसेमंद कंपनी अपने किसी उत्पाद को बड़े पैमाने पर बाजार में उतारती है, तो पहले यह सुनिश्चित कर लेती है कि वह पूरी तरह कारगर है। न जाने कैसे माइक्रोसाफ्ट से यह चूक हो गई कि इस साफ्टवेयर को लेकर आ रही शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए इसे बाजार में चलाए रखा। माइक्रोसाफ्ट एज नामक तकनीक उपयोगी और सुविधाजनक हो सकती है, मगर पूरी तरह भरोसेमंद बन जाने से पहले उसे बाजार में इतने बड़े पैमाने पर नहीं वितरित किया जाना चाहिए था। जिस एंटीवायरस की वजह से ताजा समस्या आई बताई जा रही है, उसके परीक्षण में भी कही न कहीं चूक हुई। इस साफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते सिर्फ कुछ देर में जिस तरह दुनिया भर में करोड़ों लोगों को परेशानियां और व्यावसायिक संगठनों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई होना मुश्किल है।

सर्पदंश की मार

बरसात के मौसम में जलभराव और उमस भरी गर्मी की वजह से सांप अपने बिल से बाहर निकलकर सुरक्षित ठिकाने ढूंढ़ने लगते हैं और इस कारण सर्पदंश की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनिया भर में हर साल लगभग पैंतालीस से चौवन लाख लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं, जिनमें से करीब एक लाख अड़तीस हजार लोगों की मौत हो जाती है। सर्पदंश के अधिकांश मामले अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में सामने आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सालाना तीस से चालीस लाख सर्पदंश की घटनाएं होती हैं, जिनमें से करीब पचास हजार लोगों की मौत हो जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत में पाए जाने वाले सत्तर फीसद सांप या तो जहरीले नहीं होते हैं, या फिर उनका विष मनुष्य के शरीर को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि सर्पदंश से वैश्विक स्तर पर हर वर्ष होने वाली मौतों में से करीब चालीस फीसद भारत में होती हैं।

जाहिर है कि भारत में सामाजिक और सरकारी स्तर पर जागरूकता का अभाव और व्यवस्थागत खामियां व्याप्त हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी सर्पदंश से पीड़ित को तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक के लिए ओझा के पास ले जाने की घटनाएं आमे हैं। बाद में जब पीड़ित को अस्पताल ले जाया जाता है, तब तक इलाज में देरी हो जाती है। यह भी देखा गया है कि सर्पदंश के बाद पीड़ित व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कई बार हृदयाघात से उसकी मौत हो जाती है। यों आस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सर्पदंश के इलाज के लिए एक नई कारगर दवा बनाने का दावा कर दुनिया में एक नई उम्मीद जगाई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दवा न केवल मनुष्य के शरीर में सांप के जहर के फैलने की गति को धीमा कर सकती है, बल्कि यह ऊतक एवं कोशिका के क्षय को रोकने में भी सक्षम है। मगर अपने देश के सरकारी अस्पतालों में सर्प विष-रोधी दवा की कमी से संबंधित खबरें अक्सर आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को समय पर दवा नहीं मिलने से उसकी मौत स्वाभाविक है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

धनशोधन का जटिल मायाजाल

धनशोधन का देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मगर दुनिया के कई देशों में धनशोधन रोकथाम उनकी प्राथमिकता सूची में नहीं है।

अजय जोशी

धनशोधन की प्रवृत्ति मोटे तौर पर काले धन से जुड़ी हुई है। इसका अपना एक बड़ा मायाजाल है, जिसको समझना आसान नहीं। धनशोधन में अवैध रूप से प्राप्त धन यानी काले धन को छिपा कर एक प्रक्रिया द्वारा वैध बना कर दिखाया जाता है। यह एक प्रकार का वित्तीय अपराध है, जिसमें अवैध रूप से अर्जित धन को जानबूझ कर वित्तीय और आर्थिक स्रोतों में लाया और प्रसारित किया जाता है। यहां से अपराधी कानूनी रूप से उस धन का उपयोग सामान, संपत्तियां और सेवाएं खरीदने के लिए कर सकते हैं। चूंकि यह एक प्रकार का अपंजीकृत धन है, इसलिए सरकारें उस पर कर नहीं लगा पातीं। इससे एक तरफ सरकारों का राजस्व कम होता है तो दूसरी तरफ अवैध और खतरनाक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

यह विश्वव्यापी समस्या है। अकेले यूनाइटेड किंगडम को हर वर्ष धनशोधन से सौ अरब पौंड से ज्यादा का नुकसान होता है। यूएनओडीसी यानी 'यूनाइटेड नेशंस आफिस आप ड्रग्स एंड क्राइम' का अनुमान है कि हर वर्ष दुनिया भर में धनशोधित की जाने वाली राशि वैश्विक जीडीपी के दो से पांच फीसद तक है। यह राशि 715 अरब से 1.87 ट्रिलियन यूरो के बीच है। भारत में भी धनशोधन के माध्यम से आए काले धन की एक समांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। काले धन को विदेशी बैंकों में भी जमा किया जाता रहा है। भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा किया गया काला धन एक अनुमान के मुताबिक लगभग 72 लाख 80 हजार करोड़ रुपए है। इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के बजाय आपराधिक गतिविधियों में होता है। इनमें नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, जुआ, आतंकवाद आदि गैरकानूनी गतिविधियों का वित्तपोषण करने जैसे कार्य शामिल हैं।

धनशोधन में संलग्न व्यक्ति पहले अवैध तरीके से धन प्राप्त करते हैं। इसमें अक्सर बड़ी मात्रा में नकदी जमा करना या नकदी से मूल्यवान संपत्ति खरीदना शामिल होता है, जिसे बाद में बेचा जा सके। इसमें बड़ी रकम को तोड़कर वित्तीय प्रणाली में कई छोटी जमा राशियों में डाल दिया जाता है। अपराधी ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रानिक हस्तांतरणों के माध्यम से बड़ी जमा राशियों को अलग-अलग खातों में फैला देते हैं। दूसरे चरण में अवैध रूप से प्राप्त धन को अलग-अलग खातों में और अक्सर विभिन्न देशों में स्थानांतरित कर देते हैं। फिर इसको निवेश के माध्यम से या संपत्ति खरीद कर उसका रूप बदला जाता है। तीसरे चरण में 'शोधित' धन, जो अब छिपा हुआ है और जिसका अवैध स्रोत तक पता नहीं लगाया जा सकता, उसको औपचारिक अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाता है।

धनशोधन की प्रक्रिया में काले धन की प्राप्ति और उसके निपटारे के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी द्वारा लेनदेन आजकल काफी प्रचलित है। इसमें गुमनाम खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा आनलाइन नशीली दवाओं और सेवाओं का व्यापार किया जाता है। इसमें वित्तीय लेनदेन में होने वाली आपराधिक गतिविधियों का पता लगाना बहुत

मुश्किल होता है। इसी प्रकार व्यवसायी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के चालान की राशि कम या अधिक दिखाई जाती है। इनमें अंतर की राशि अपराधी नकद प्रदान कर सकते हैं, जिसे वे फिर इलेक्ट्रानिक माध्यम से वापस जमा करवा कर उसको वैध दिखा सकते हैं। धनशोधन

> **धनशोधन की रोकथाम के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय शामिल है। वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय अपराध से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग और भागीदारी करने की आवश्यकता है। धनशोधन से निपटने के लिए व्यक्तियों में शिक्षा और जागरूकता संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सहायक होती है, इस दिशा में काम किया जाना सहायक हो सकता है। धनशोधन के मामलों में धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत अपराध से जुड़े मामलों की तुरंत जांच, सुनवाई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने जैसे प्रभावी उपायों की भी जरूरत है।**

के अंतर्गत फर्जी कंपनी, जिन्हें 'शेल कंपनियां' भी कहा जाता है, उनमें निवेश या लेनदेन द्वारा धन-शोधन का तरीका भी काफी प्रचलित है। इन फर्जी कंपनियों का अस्तित्व केवल कागजों पर होता है। कंपनी के नाम पर कर्ज और सरकार से करों में छूट भी लेते हैं। इन सब फर्जी कामों के माध्यम से बहुत-सा काला धन जमा कर लेते हैं। अगर कोई तीसरा पक्ष वित्तीय अभिलेखों की जांच करना भी चाहे, तो उसको धन के स्रोत और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेज दिखा दिए जाते हैं। ये कंपनियां निवेशकों को धोखा देने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में हेरफेर करती और फर्जी मुनाफा दिखाती हैं। इन कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री आदि के कागजी लेनदेन के मध्यम से भी धनशोधन किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) समय-समय पर फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई करती है। सेबी ने ऐसी करीब पांच लाख कंपनियों की पहचान की है और शुरुआती तौर पर इनमें से 331 कंपनियों की सूची जारी की है। इनमें जो कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, उनके कारोबार पर प्रतिबंध लगाया गया है। देश में धनशोधन की रोकथाम हेतु धनशोधन रोकथाम कानून 2005 लागू है। इस कानून के जरिए आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, धनशोधन में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और धनशोधन संबंधी अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है। सरकार का दावा है कि धनशोधन मामलों में जांच और कार्रवाई पिछले दस वर्षों में छियासी गुना बढ़ी है। ईडी ने पिछले दस वर्षों के दौरान धनशोधन रोकथाम कानूनों के तहत 5155 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती भी लगभग पच्चीस गुना बढ़ी है।

धनशोधन का देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मगर दुनिया के कई देशों में धनशोधन रोकथाम उनकी प्राथमिकता सूची में नहीं है। इसलिए धनशोधन में शामिल जटिलताओं के चलते अपराधियों की पहचान करना और उन पर मुकदमा चलाना एक बड़ी चुनौती है। वित्तीय संस्थान धनशोधन से निपटने में सहायता कर सकते हैं। वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि वैध व्यक्तियों से कारोबार किया जा रहा है या नहीं। आंतरिक नियंत्रणों की व्यवस्था और विभिन्न व्यावसायिक व्यवहारों का सटीक दस्तावेज बनाए रखना तथा उनको एक निश्चित समयावधि तक संधारित रखना भी बहुत सहायक हो सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 'वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी' शीर्षक अपनी रपट में सिफारिश की है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान सूचना साझा करने में सहयोग करें।

धनशोधन की रोकथाम के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय शामिल है। वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय अपराध से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग और भागीदारी करने की आवश्यकता है। धनशोधन से निपटने के लिए व्यक्तियों में शिक्षा और जागरूकता संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सहायक होती है, इस दिशा में काम किया जाना सहायक हो सकता है। धनशोधन के मामलों में धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत अपराध से जुड़े मामलों की तुरंत जांच, सुनवाई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने जैसे प्रभावी उपायों की भी जरूरत है, तभी इसकी रोकथाम संभव है।

सुख के सपनों का दुख

मनोज कुमार

कहते हैं कि सुख और दुख जीवन में परछाई की तरह होते हैं। दोनों का समय बंधा हुआ है। आज दुख है तो कल सुख हमारे द्वार आएगा। जो आज सुखी है, उसके जीवन में दुख चुपके से प्रवेश कर जाएगा। दुख के अर्थ अनेक हैं। वह हमारी सेहत का हो सकता है। वह रोजगार को छीन सकता है, रिश्तों में खटास ला सकता है या दुख हमारे सपने को तोड़ सकता है। मगर सुख की एक परिभाषा है चेहरे पर मुस्कराहट। जो आदमी प्रसन्न है, वह सुखी है और जो सुखी है वह प्रसन्न है। इससे इतर एक और सवाल मन में आता है कि आखिर दुख क्यों उपजता है? शायद किसी साधारण व्यक्ति के लिए एक परिभाषा हो सकती है कि जब अपने मन का न हो तो दुख, लेकिन हकीकत यह है कि दुख से बड़ा दुख सुख के सपने देते हैं। हम सपने बुन लेते हैं। कई बार हमारे जीवन में यह सपना आता है कि हमारी शिक्षा के मुताबिक ओहदा और सम्मान मिले, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है और हम दुखी हो जाते हैं। यहां दुख की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि सुख के सपने की कल्पना पूरी नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं।

ऐसे लोग आसपास देखे जा सकते हैं, जिनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही, लेकिन आज वे खुश हैं। यह खुशी उनके सपनों के सच हो जाने की खुशी है। जिस जीवनसाथी से जीवन भर उनकी नहीं बनी होगी, अचानक उनके प्रति चिंता या उनके हवाले खुद को छोड़ देना सुख नहीं है, बल्कि सुख के सपनों को पूरा करना है। एक सच यह भी है कि जब उस दंपती के बीच जीवनभर तनातनी चल रही होगी, तब वे आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं रहे होंगे। सत्ता संस्थानों और ख्याति की कल्पना की जाती है, उससे भी बहुत वास्ता नहीं होगा। मगर जीवन का पहिया घूम जाए तो और सुख के सपने सच होने लगते हैं। धन, सत्ता और ख्याति पास चली आती है और फिर सुख भी पहलू में आ जाते हैं। दुख का सुख में बदलना शायद इसे ही कहते हैं।

हम जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, उसमें अगर किसी महिला जीवनसाथी को यह कहा जाए कि पति के जिंदा और स्वस्थ रहने की इच्छा अपने जीवन के अनावश्यक कष्टों की आशंका की वजह से की जाती है, तो यह शायद आम धारणा के मुताबिक ही होगा और महिला जीवनसाथी इसे सच भी माने। निर्भरता की स्थितियां कई बार इस तरह सोचने पर मजबूर करती हैं। इस तरह की बातों में सुख और दुख का दोनों पलड़ा समान है, क्योंकि महिला के सुख के सपने टूट नहीं रहे हैं और दुख की आशंका को उसने जाहिर कर दिया है। हमारे समाज में अनेक परिवार हैं जिनमें लोग गफलत में ही सही, सुख के सपने के साथ जीवन बसर कर लेते हैं। अगर रिश्ते के लिए सोचा और किया जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। मगर यह कहा जाए कि कोई पैसे के लिए उसका खयाल रख रहा है तो इस तरह का दंभ जीवन में एक नया दुख दे सकता है।

दुख को सुख के सपनों में परिवर्तित करने का एक अवसर तब आता है, जब बच्चे उनका साथ छोड़कर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। एकाकीपन में जो साथ होता है, वह सुख और दुख की किसी परिभाषा से परे होता है। यहां परस्पर जरूरत दोनों को साथ लेकर आता है। खाना से लेकर दवा तक इंतजाम करना होता है और यही जरूरतें सुख और दुख की नई परिभाषा गढ़ती हैं। इसे हम अपने अनुरूप अपनी परिभाषा में ढाल सकते हैं।

सुख के सपने टूटने का मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाया जाए तो बेहताशा उम्मीदों का टूट जाना और निराशा में मौत को गले लगाना है। देश के किसी भी राज्य में खुदकुशी के आंकड़ें देखे जाएं तो सर्वाधिक निराश और हताश युवा मिलेंगे जो जीवन को खत्म करना सबसे आसान समझते हैं। उनका जीवन अभी शुरू हुआ है और उनके जीवन में अच्छे अंकों से पास नहीं होना या मनमर्जी के मुताबिक नौकरी नहीं मिलना या बेरोजगारी से तंग आकर प्रेम का टूट जाना उनका दुख है। यह वही स्थिति है जहां दुख ने नहीं, सुख के सपनों ने हमेशा इस पीढ़ी को दुखी किया है। ऐसे में पिता का पीठ पर हाथ और मां का दुलार उन्हें ऐसे दुख से उबार सकता है। यहां दुख और निराशा में भी भेद करने आना चाहिए। दुख आने पर इसका निदान हो सकता है, लेकिन निराशा का कोई मरहम नहीं. आज समाज में ऊंचे सपने और टूटते सपनों के बीच युवा मन टूट रहा है।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> **एकाकीपन में जो साथ होता है, वह सुख और दुख की किसी परिभाषा से परे होता है। यहां परस्पर जरूरत दोनों को साथ लेकर आता है। खाना से लेकर दवा तक इंतजाम करना होता है और यही जरूरतें सुख और दुख की नई परिभाषा गढ़ती हैं। इसे हम अपने अनुरूप अपनी परिभाषा में ढाल सकते हैं।**

एक पुरानी लोककथा है, जिसमें पिता-पुत्र बाजार से निकलते हैं और पुत्र हाथी देखकर मचल उठता है। गरीब पिता हाथी का भाव पूछता है, क्योंकि दो पैसे का हाथी उसे महंगा लगता है। कुछ साल गुजरने के बाद यही दृश्य दोहराया जाता है और पिता फिर हाथी का भाव पूछता है तो उसे दो हजार रुपए बताया जाता है। पिता खुशी-खुशी बेटे के लिए हाथी खरीद लेता है। बेटा पिता से सवाल करता है कि दो पैसे का हाथी लेने से मना कर दिया था और आज दो हजार का हाथी आप ले रहे हैं। पिता ने एक पंक्ति में समझाया कि तब दो पैसे भी हमारे लिए दो हजार के समान थे। यही जीवन की रीत है और सुख और दुख चलता रहता है।

जोखिम के खानपान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने और उनके स्थान पर पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने का दिशा-निर्देश जारी किया है। भोजन का हमारे मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे मन-मस्तिष्क में उसी प्रकार के भाव उठते हैं। आजकल डिब्बाबंद भोजन और जंक फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। डिब्बाबंद भोजन शरीर में मोटापा बढ़ाने के साथ कई ऐसी बीमारियों की जनक है, जो प्रारंभिक दौर में पहचान में नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के बाद वही बीमारियां हमारे जीवन के लिए नासूर बन जाती हैं। सरकार को कानून बनाकर सभी डिब्बाबंद खाद्य सामग्रियों पर वसा, नमक और चीनी एवं अन्य सामग्रियों की मात्रा का विवरण पैकेट पर उपलब्ध कराना अनिवार्य बना देना चाहिए, ताकि खरीदने से पहले लोग यह जान सकें कि इन खाद्य सामग्रियों में कौन-सी मात्रा किस अनुपात में मिलाई गई है। डिब्बाबंद खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए।

- हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पर्यावरण के लिए

तथाकथित आधुनिक होते मानव ने अपनी अनियंत्रित इच्छाओं और जरूरतों के चलते पर्यावरण यानी अस्तित्व के मूल को गंभीर चोट पहुंचाई है। आजीविका, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि कुछ क्षेत्र हैं, जहां पर्यावरणीय क्षति अधिक प्रबलता और मुखरता से दिख रही है। यह सचेत होने का समय है और इस जटिल समस्या का एकमात्र समाधान वृक्षारोपण है। हरित आवरण बढ़ाकर और मानवीय गतिविधियों की सीमाएं तय कर ही 'जलवायु दोष' के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। भारत का जलवायु 'मानसून' पर निर्भर है। जुलाई से सितंबर तक यह पूरे देश में दस्तक देता है। इस दौरान धरती विशेष रूप से संभावनाओं को फलित करती है। झाड़ियां, पौधे, वृक्ष इस मौसम में आशातीत रूप से प्रगति करते हैं। हमें समझना है और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपने 'पर्यावरणीय कर्तव्यों' का पालन करना है, ताकि हम और हमारी आगामी पीढ़ियां जीवन की मूल दिशाओं से अनभिज्ञ न रहे, परेशान न हों।

- जोगिंद्र भारद्वाज, मायूरपुर, दिल्ली

किसान का दुख

किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। पूर्व में हुए किसान आंदोलन में ऐसी स्थिति बनी थी कि अंत में सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा और प्रधानमंत्री ने किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। किंतु जब मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है। 'आंदोलन और अवरोध' (संपादकीय, 13 जुलाई) में उल्लेख है कि हरियाणा सरकार आंदोलनकारियों को दिल्ली जाने में बाधक बन रही है। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि किसान, व्यापारी और आम लोगों के लिए रास्तों को खुला रखे और आंदोलनकारी भी रास्ते में बाधक न बनें अर्थात आंदोलन के दौरान रेल और सड़क मार्ग पर न हो और जाम न लगे। इसी तरह किसानों को भी दिल्ली जाने पर रोक नहीं लगाएं, क्योंकि किसान कोई अवांछित लोग नहीं हैं। वे हमारे देश के ही नागरिक हैं। जरूरत है किसानों की मांगों को सुनने और पूरा करने की।

- बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

किस ओर समाज

'बेटियों की जगह' (संपादकीय, 12 जुलाई) पढ़ा। दिल्ली में एक पिता के द्वारा एक पुत्र की चाह में अपनी दो मासूम बच्चियों की हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। आज के युग में लड़कियां हर क्षेत्र में चाहे शिक्षा हो, खेल हो, राजनीति हो, सेना हो और चाहे विज्ञान हो, चारों ओर अपना परचम लहरा रही हैं। हर पुरुष को एक स्त्री ही जन्म देती है! ऐसे में खुद पिता अपनी मासूम बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन कर दे, तो यह बेहद दुखद घटना है। समाज किस ओर जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। हजारों मासूम बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, हजारों को पैदा होने के बाद! छोटी-छोटी मासूम बच्चियों से बलात्कार किए जाते हैं। दहेज के नाम पर उनकी हत्याएं होती हैं। बच्चियों को बचाने की जिम्मेदारी सरकारों को तो लेनी ही होगी। सिर्फ 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के नारे से कुछ नहीं होगा।

- चरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 20 जुलाई 2024

पहचान का प्रश्न

छोटी-छोटी बातों पर न बढ़े कड़वाहट

जिसे उत्तर प्रदेश के एक जिला प्रशासन का स्थानीय स्तर पर लिया गया फैसला माना जा रहा था, वह तेज होते विरोध के बीच न केवल पूरे राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में भी लागू कर दिया गया। इस आदेश के मुताबिक, कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर दुकान लगाने वाले तमाम लोगों के लिए अपनी पहचान सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

कांवड़ियों की सेवा सबका हक

आदेश पर असमंजस | इस आदेश से किस तरह का असमंजस फैला है, इसका अंदाजा BJP के ही एक प्रमुख नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया से मिलता है। शुरू में इस आदेश के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा, 'कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश... छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं।'

विरोध का उलटा असर | विरोध करने वालों में नकवी अकेले नहीं थे। विपक्षी दलों के अलावा NDA के सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से भी इसके विरोध की आवाज उठी थी। माना जा रहा था कि विरोध के बाद जिला स्तर पर हुए इस फैसले को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन कुछ घंटों के अंदर पूरे राज्य में इस आदेश को लागू करने का निर्णय घोषित हो गया। इसके बाद नकवी भी अपना रुख पलटते दिखे। उनका कहना था कि शुरू में उस फैसले ने कुछ कन्फ्यूजन फैलाया था, लेकिन अब सरकार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इस फैसले का विरोध करने की अब कोई वजह नहीं है।

आर्थिक बहिष्कार का खतरा | विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर चाहे जैसा भी विचार मंथन हो रहा हो, यह आदेश आबादी के एक बड़े हिस्से में भ्रम और आशंका पैदा कर सकता है। एक समुदाय विशेष के मन में यह भाव गहरा हो सकता है कि सरकार धंधा-पानी करने के उसके अधिकार पर कुठाराघात करना चाहती है। चाहे जितने भी मासूम अंदाज में पेश किया जाए, पहचान बताने के इस आदेश का असर खास समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के ही रूप में सामने आएगा। यह आशंका भी निराधार नहीं कि अलग पहचान वाले दुकानदारों पर कुछ असामाजिक और सांप्रदायिक तत्व कांवड़ियों के वेश में हमला कर दें, उनकी दुकाने लूटने लग जाएं।

शुचिता का तर्क गलत | कांवड़ियों की शुचिता के तर्क के पीछे यह गलत मान्यता काम कर रही है कि किसी अन्य समुदाय के हाथ का छुआ खाने से किसी श्रद्धालु का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। कानून व्यवस्था का तर्क भी उचित नहीं क्योंकि इससे पहले इस आदेश के बगैर भी कांवड़ यात्रा सुरक्षित माहौल में होती रही है। संक्षेप में, ऐसे आदेश हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। इन्हें वापस लेने में देर करना ठीक नहीं।

दो दूनी चार

निवेश में कुछ नया

रमेश तिवारी

रिटेल इन्वेस्टरों का जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना चिंता का सबब बनता जा रहा है। ये माना जा रहा है कि लोगों को रिस्क लेने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनका निवेश नियम-कायदे के दायरे में होना चाहिए। इसी सोच के साथ अभी हाल में एक नया प्रॉडक्ट लाने का प्लान बनाया गया, जिसे फिलहाल न्यू असेट क्लास का नाम दिया गया है। इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए लाया जा रहा है जो ज्यादा रकम निवेश कर सकते हैं और रिस्क भी उठा सकते हैं।

न्यू असेट क्लास को म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियां ही बेच सकेंगी। अभी तक फंड चलाने वाले मैनेजरों को कई तरह के रिस्क लेने से रोका जाता है, लेकिन नए असेट क्लास में उन्हें इसकी इजाजत दी जा सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जो प्लान बनाया है, उसके मुताबिक नया प्रॉडक्ट म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बीच की चीज है। म्यूचुअल फंड आम लोगों के लिए है, जहां सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। पीएमएस अमूमन हाई नेटवर्थ वाले निवेशकों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करता है, जिससे जुड़ने के लिए जेब में कम से कम 50 लाख रुपये होने चाहिए। जो न्यू असेट क्लास लाया जा रहा है, उसके लिए जेब में कम से कम 10 लाख रुपये होने चाहिए। यानी इसमें निवेशकों की संख्या का दायरा बढ़ जाएगा।

म्यूचुअल फंडों का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिये इन्होंने लोगों को ज्यादा रिस्क लेने से बचाया है। माना जा रहा है कि नए असेट क्लास में जो भी रिस्क होगा, उसे भी फंड हाउस नए-नए तरीकों से मैनेज कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि निवेशकों के सामने ढेर सारे विकल्प होने चाहिए। हर निवेशक अपनी क्षमता के हिसाब से रिस्क ले सके। लेकिन हाल के समय में बाजार में इस तरह के पीएमएस आ गए थे, जहां नियम कायदे नहीं चलते थे। बिना नियम कायदे के रिस्क देखते हुए हाई नेटवर्थ वाले निवेशक म्यूचुअल फंडों में भी पैसा लगा रहे थे।

मुमकिन है कि न्यू असेट क्लास के सामने आने पर पीएमएस के कारोबार को झटका लगे। क्योंकि नए सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी निवेशक के पास उपलब्ध होगी। इस नए प्रॉडक्ट में निवेश का पैसा कहां लगाया जाएगा, इसमें कितना खर्च वसूला जाएगा, इस बारे में जानकारी धीरे-धीरे सामने आएगी। इसमें म्यूचुअल फंडों के मुकाबले ज्यादा खर्च वसूला जा सकता है। फंडों के मुकाबले पैसा निकालने में ज्यादा बंदिशें भी हो सकती हैं, क्योंकि निवेश हाई रिस्क कैटिगरी में होगा। इन दिनों घरेलू बचत का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में जाता दिख रहा है। म्यूचुअल फंडों में निवेश रिकॉर्ड बना रहा है। इसकी वजह ये है कि लोगों को इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न दिख रहा है। अब लोग म्यूचुअल फंड से आगे जाना चाहेंगे। ज्यादा रिटर्न की चाह में वो न्यू असेट क्लास में पैसा लगाएंगे। लेकिन इस नए प्रॉडक्ट को लोग समझेंगे, इसमें काफी वक्त लग सकता है। म्यूचुअल फंडों को आज लोग समझने लगे हैं, लेकिन इसमें 30 साल से ज्यादा वक्त लग गया। आज जब बाजार लगातार ऊपर चढ़ रहा है, तो लोग भले ही ज्यादा रिस्क वाले नए असेट क्लास में पैसा लगाने को राजी हो जाएं, लेकिन जब बाजार गिरेगा तो देखना होगा कि निवेशकों का क्या रुख होता है।

ऑफ दि ट्रैक

जेली जैसी बैटरी

दिलीप लाल

डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया, मिर्गी और अन्य गंभीर मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थिरेपी (ECT) कारगर उपाय है। इसे शॉक थिरेपी भी कहते हैं। मरीज के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है। इससे थोड़ी देर के लिए मरीज को दौरे आते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब दवाएं और मनोचिकित्सा फेल हो जाती हैं। लेकिन, इसका विकल्प तलाश लिया गया है, जो ज्यादा कारगर है। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जेली जैसी बैटरी का आविष्कार किया है। यह जेली जैसी ही है, चिपचिपी और इसे खींचा भी जा सकता है। इसके जरिए आसानी से दिमाग में बिजली का करंट दिया जा सकता है। यह रिसर्च अमेरिकी पत्रिका 'साइंस एडवांसेस' में प्रकाशित हुआ है। बॉडी इंप्लांट में सबसे बड़ी परेशानी यह आती है कि इंसानी शरीर किसी भी नई चीज को आसानी से स्वीकार नहीं करता। लेकिन, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जेली बैटरियां इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। इनकी सबसे विशेषता है कि मुलायम होती हैं और ह्यूमन टिशू के मुताबिक ढल सकती हैं। ऐसे में भविष्य में बायोमेडिकल इंप्लांट्स में इनके इस्तेमाल की बहुत संभावनाएं हैं। इनकी एक और बड़ी क्वालिटी है, खुद से खुद को ठीक कर लेना। मान लीजिए कि किसी वजह से इनका आकार बिगड़ जाता है, तो ये वापस शेप में आ सकती है।

लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद

हरियाणा में होगा सियासी दंगल

राज कुमार सिंह

हरियाणा में सत्ता के लिए चुनावी लड़ाई तो अक्टूबर में होगी। लेकिन जुबानी जंग और दांव-पेच शुरू हो चुके हैं। 2024 के लोकसभा की दस में से नौ सीटें जीतने के बाद हुए विधानसभा चुनावों में BJP ने पहली बार हरियाणा में सरकार बनाई थी। वह भी अकेलेदम बहुमत हासिल कर, वरना तो राज्य में हमेशा वह देवीलाल और बंसीलाल के दलों की बैसाखी ही बनती रही।

बहुमत नहीं मिला | 2019 में भी BJP लोकसभा की सभी दस सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई। तब उसे देवीलाल परिवार के ही एक धड़े द्वारा नवगठित दल जननायक जनता पार्टी (JJP) से गठबंधन करना पड़ा था। अप्रत्याशित रूप से चुनाव में JJP को 10 सीटें मिली थीं और इस समर्थन की एवज में BJP को दुष्यंत चौटाला को उप-मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था।

कड़े मुकाबले के आसार | अब जबकि हालिया लोकसभा चुनाव में BJP दस में से पांच सीटें ही जीत पाई है, विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं। कांग्रेस इस बार पांच सीटें जीत गई। कुरुक्षेत्र सीट गठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ने के कारण कांग्रेस नौ सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी।

जीत का भरोसा | जाहिर है, इस सफलता के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस, खासकर हुड्डा खेमे के तेवरों से तो लगता है कि वे सत्ता में वापसी तय मानकर चल रहे हैं, लेकिन चुनावी रण इतना आसान भी नहीं होता। 2019 में भी कांग्रेस ने ऐसे ही तेवरों के साथ विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। गुटबाजी से ग्रस्त कांग्रेस की एकता की तस्वीर पेश करने के लिए आलाकमान ने पार्टी छोड़ गए अशोक तंवर की जगह कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो किरण चौधरी की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने।

पार्टी में खेमेबाजी | वैसे, 2014 विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने INLD (इनेलो) को मुख्य विपक्षी दल बनाया था और अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष बने थे, लेकिन पार्टी में मची भगदड़ के बाद स्थितियां बदल गईं। बेशक 2014 के मुकाबले कांग्रेस ने 2019 में BJP को जोरदार टक्कर दी, लेकिन उससे नौ सीटें कम हासिल कर पाई। BJP की छह सीटें कम करने पर अपनी पीठ थपथपाते हुए हुड्डा खेमे ने सफाई दी कि दूसरे गुटों के दबाव में गलत टिकट बंटवारे के कारण पार्टी सरकार बनाने से चूक गई, जबकि विरोधी गुट ने यही आरोप हुड्डा खेमे पर लगाया।

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कुछ सेवाओं में 10% आरक्षण की घोषणा की है

क्या सीन है

- कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत
- लोक-लुभावन योजनाओं पर BJP का दांव
- विरोधी वोट बंटने से BJP को होगा फायदा

बड़े नेताओं ने छोड़ा साथ | 2019 के मुकाबले 2024 में हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य कितना बदला हुआ है? पहला बड़ा बदलाव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन है। दूसरा BJP से गठबंधन टूटने के बाद JJP का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ये बदलाव कांग्रेस के लिए सकारात्मक हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी का पार्टी छोड़ना अच्छी खबर नहीं है। कुलदीप पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं तो किरण एक और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू। दोनो ने हुड्डा खेमे के चलते कांग्रेस छोड़ी।

मनोहर की भूमिका | BJP में भी काफी कुछ बदला है। 2014 में बहुमत मिलने पर मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद के लिए आलाकमान की चौंकाने वाली पसंद थे, लेकिन 2019 में वह स्वाभाविक पसंद बने। कई परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाबाशी पाने वाले मनोहर लाल ने नौ साल से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद स्वयं ही इस साल मार्च में पद छोड़ दिया।

OBC वोटरों पर नजर | पिछली लोकसभा में कुरुक्षेत्र से सांसद रहे नायब सिंह सैनी को पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर मुख्यमंत्री। यह पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए किया गया। कुछ ही दिन पहले राई के विधायक मोहन लाल बड़ौली को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनकी तात्पोशी का संकेत साफ है कि BJP फिर जाट-गैर जाट के आजमाए हुए समीकरण पर चुनाव लड़ने जा रही है।

सरकार की कोशिश | ऐसा नहीं कि BJP को इस बार कड़े चुनावी मुकाबले का आभास नहीं है। विपक्ष का मुख्य मुद्दा बनी अग्निपथ योजना के अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार की कुछ सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण और अन्य सेवाओं में आयु सीमा में छूट समेत युद्धस्तर पर लोक-लुभावन योजनाओं की घोषणा दरअसल चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा है। केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद हरियाणा की सत्ता में BJP की हैट्रिक को एकमात्र लक्ष्य बनाने वाले मनोहर लाल की भी इसमें बड़ी भूमिका बताई जाती है।

विरोधी वोट बंटेंगे | असल में, राज्य में संभावित बहुकोणीय मुकाबला BJP की राह आसान बना सकता है। अब AAP अकेले लड़ेगी या 2019 लोकसभा चुनाव की दोस्त JJP से हाथ मिलाएगी, यह तो देखना होगा। लेकिन INLD और BSP के गठबंधन करने से त्रिकोणीय मुकाबला तो तय ही गया है। INLD 53 और BSP 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस अलायंस का जो भी असर हो, लेकिन इसे, JJP और AAP को मिलने वाले वोट होंगे सत्ता विरोधी ही। यानी सत्ता विरोधी वोटों के बंटने का लाभ BJP को ही मिलेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अन्नदाता भारत

आजादी के बाद अनाज के संकट से जूझ रहा भारत आज इस स्थिति में है कि कई दूसरे मुल्कों का पेट भर रहा। ग्लोबल फूड ग्रेन एक्सपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी करीब 8% है। जानते हैं कि भारत कैसे फूड सुपरपावर बन सकता है :

AI image

उत्पादकता बढ़ानी होगी

दूसरे सेक्टर की तुलना में खेती में उत्पादकता अब भी बहुत कम है। चीन से तुलना करें तो हमारे पास एक तिहाई अधिक खेत हैं, लेकिन मूल्य के हिसाब से उपज होती है केवल तिहाई भर। खेती में लगभग 26 करोड़ लोग लगे हैं।

इंफ्रा में निवेश

खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश हर साल करीब 6% अनाज, 12% सब्जियां और 15% फल खराब हो जाते हैं। फैसिलिटी पर्याप्त नहीं रहने से

टेक्नॉलजी का सहारा

भारत में किसानों के पास जोत छोटी है। इस वजह से मशीनों का इस्तेमाल करने में मुश्किल आती है। लिहाजा तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारे देश में उपज का 10% हिस्सा ही प्रोसेस्ड होता है, जबकि ब्राजील में यह आंकड़ा 70% और थाइलैंड में 30% है।

रिसर्च को बढ़ावा

फूड सब्सिडी पर सरकार हर साल करीब 2 ट्रिलियन रुपये खर्च करती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी पर भी करीब इतनी ही रकम जाती है। इसकी तुलना में रिसर्च और डिवेलपमेंट पर केवल 95 अरब रुपये लगाए जाते हैं। यह कृषि GDP के 0.7% से भी कम है।

कीमतों पर चिंता बेकार

भारत में जब भी अनाज, फल-सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उस दौरान निर्यात पर रोक लग जाती है। जब महंगाई से दूसरे सेक्टर को फायदा हो रहा है, तब कृषि पर बंदिश सही नहीं।

प्रस्तुति : शैलेंद्र पांडेय

www.nbt.in

शिक्षकों को कैसे सुधारूं

आजकल शिक्षकों के बीच ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम को अनिवार्य बनाए जाने के सवाल पर काफी असंतोष दिख रहा है। हम सबके जीवन में कुछ बेहतरीन अध्यापक रहे हैं, जिनकी हमें गढ़ने में निर्णायक भूमिका रही है। ऐसे शिक्षकों का हम पर पूरी जिंदगी प्रभाव भी बना रहता है। लेकिन जब ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम के विरोध में पूरा शिक्षक समुदाय खड़ा नजर आता है तो यह सवाल मन में जरूर कुलबुलाता है कि क्या शिक्षकों के बारे में समाज के एक हिस्से में बनती ऐसी धारणा में सचमुच दम है कि वे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते, जितनी उन्हें लेनी चाहिए?

बहरहाल, इन्हीं खबरों ने मुझे एक पुरानी घटना याद दिला दी। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर आयोजित एक सेमिनार में गई थी। वहां कई मुद्दे उठे और बैठ गए। लेकिन शिक्षा जगत की स्थिति को बयान करता एक युवा वक्ता का बयान जेहन में ऐसा बैठा कि बरसों बाद भी धुंधला नहीं पड़ा है। उसका नाम याद नहीं है, पर वह प्रदेश के ग्राम प्रधानों के संघ का प्रधान था। यानी प्रधानों का भी प्रधान। उसने कहा, 'ग्राम प्रधान होने के बाद भी मैं आज मात्र अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने गांव की सुख-सुविधा और सरल-सहज जीवन छोड़कर, गोमतीनगर (लखनऊ) में किराए का घर लेकर रह गया हूं। गांव से बाहर निकलना मेरी महत्वाकांक्षा नहीं, मजबूरी है। मैं चाहता था, गांव इतने तो सुधर जाएं कि मेरे बच्चों को गांव में ही बेहतर शिक्षा मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 'मैं उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं और मैं जानता हूं, वहां आज भी पढ़ाई नहीं होती। मजेदार बात है, मेरे माता-पिता दोनों सरकारी अध्यापक रहे हैं। वाकया तब का है, जब मैं बच्चा नहीं रह गया था। स्कूली शिक्षा तो पूरी कर ही चुका था, प्रधान भी निर्वाचित हो चुका था।

खुद अपनी आंख से

मधु चतुर्वेदी

एक दिन मां-बाप में काम-वाम को लेकर झगड़ा हो गया। मां बोल रही थी, 'अपने काम हमें न गिनाओ। तुम काम ही क्या करते हो? वहां बैठे बस पॉलिटिक्स करते हो, कभी चार पीरियड पढ़ाए हो?' ताव खाए पिताजी बोले, 'मेरा मुंह न खुलवाओ, सब खेल पता है तुम्हारा! तुम कौन से रोज जाती हो, सब अध्यापिकाओं-प्रधानाचार्य की मिलीभगत है, आधी आएंगी, आधी छुट्टी मनाएंगी, सब पता है, बिना तारीख वाले छुट्टी के आवेदन सबके वहां रखे रहते हैं, कोई औचक निरीक्षण हो जाए तो तुरंत उस दिन की तारीख डालकर अवकाश पर दिखा दिया जाता है, पूरी चौकस व्यवस्था है न, नौकरी आराम से चला रही हो'।

मैंने अपने हाथ का मोबाइल दिखाते हुए कहा, 'समझ लो! हमने आप लोगों की पूरी बात रेकॉर्ड कर ली है।' इसे मेरी प्रधानी का असर कहिए या उनकी शर्मिंदगी या फिर भय, लेकिन असर तत्काल दिखा। वे उस समय तो सकपका कर चुप हो ही गए, उसके बाद वे दोनों ड्यूटी पर भी नियमित हो गए। लेकिन घर की बात अलग है, सचाई यही है कि शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार मैं नहीं कर पाय। अरे उसी गांव का तो प्रधान हूं, जहां के शिक्षकों के हाथों पढ़ा हूं। क्या कर सकता हूं, विद्यालय जाकर, बस पैर छूकर आ जाता हूं। कौन सुधारेगा? क्या वे मेरी बात सुनेंगे?'

चलते-चलते...

जिन बच्चों के परिवार अक्सर घर बदलते हैं, उनके अवसाद में घिरने की आशंका बढ़ जाती है। ब्रिटेन की प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि घर बदलने से माहौल बदलता है और बच्चों को बार-बार नई जगह एडजस्ट होना पड़ता है। इसका सीधा असर होता है उनके दिमाग पर। यह स्टडी हाल ही में JAMA Psychiatry पत्रिका में प्रकाशित हुई है।

मुसलमानों को है बेरुख़ी का डर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का हक है। इसे लेकर लोगों में बहस चल रही है। लेकिन मुस्लिम समाज यहीं तक सीमित नहीं है। CSDS के प्रो. हिलाल अहमद की इसी महीने मुस्लिम समाज के वर्तमान पर 'A Brief History of the Present: Muslims in New India' किताब आई है। इस किताब और मुस्लिम समाज के हालात पर उनसे बात की राहुल पाण्डेय ने। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :

सप्ताह का इंटरव्यू

प्रो. हिलाल अहमद

■ मुस्लिम महिलाओं के गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है?

मैं निजी रूप से इस फैसले का स्वागत करता हूं। मेरा मत है कि लैंगिक समानता का कानूनी तौर पर सांवैधानिक होना सामाजिक न्याय की स्थापना की पहली शर्त है। मेरी यह निजी राय है, जिसकी अपनी सीमा है। इस विषय पर अभी काफी शोध होना बाकी है, तभी हम इस फैसले के सामाजिक प्रभावों पर विधिवत टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे।

■ आपने इस विषय पर काम भी तो किया है। क्या उससे कोई रोशनी नहीं निकलती?

मैंने इस विषय पर 2021 में एक पुस्तक का संपादन किया था। तब से अब तक काफी चीजें बदल गई हैं। मेरी नई पुस्तक इस विषय को सीधे संबोधित नहीं करती है। वह मुस्लिम सामाजिक-राजनीतिक विमर्श को देखने का नजरिया देने की कोशिश करती है।

■ किताब का पहला अध्याय एक रिसर्चर की मुस्लिम पहचान के सवाल को लेकर शुरू होता है..

मेरा मानना है कि व्यक्ति की केवल एक पहचान नहीं होती। एक ही समय में अपनी कई सारी पहचानों के साथ हम जिंदा रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन सभी पहचानों के बीच तारतम्य देखा जाए। एक समुदाय विशेष पर रिसर्च कर रहे शोधार्थी के लिए जरूरी है कि वह उस समाज से एक उसूली दूरी बना कर रखे, उस समाज के प्रति बौद्धिक आलोचनात्मक रवैया रखे और अपनी रिसर्च प्रक्रिया को अपने पाठकों के सामने ईमानदारी से प्रस्तुत करे।

■ किताब में मुस्लिम राजनीति की एक जटिल तस्वीर पेश की गई है। ऐसा क्यों?

मुस्लिम राजनीति का संबंध सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति भी एक तरह से मुस्लिम राजनीति का ही एक स्वरूप है। दुर्भाग्यवश हमारा सार्वजनिक विमर्श इतना विभाजित है कि इसमें राजमार्ग की राजनीति की बात निकल सी गई है। मुस्लिम राजनीति अपने आप में बहुआयामी है। मुसलमानों में लोकतंत्र और संविधान के लिए जबरदस्त उत्साह है, वे राज्य से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं। लेकिन वे इस बात से आशंकित हैं कि राजनीतिक वर्ग उन्हें लेकर पूरी तरह से उदासीन हो गया है। एक ओर BJP है जो सबका साथ सबका विकास की बात करके मुस्लिम पहचान पर सीधे बात करने से परहेज करती है। दूसरी ओर अन्य दल मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी बनाए रखना चाहते हैं ताकि उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण का इल्जाम न लगे। इस उदासीनता के बावजूद मुस्लिम समुदायों में राजनीतिक विश्वास बना हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की इसी ताकत को मैंने उजागर करने की कोशिश की है। यहां मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि मुस्लिम राजनीति की यह जटिल तस्वीर मेरी अपनी कल्पना से नहीं निकली है, यह मेरे पिछले पांच वर्षों के शोध और सर्वेक्षणों का परिणाम है।

■ आपकी किताब हिंदुत्व संविधानवाद की बात करती है। इसे जरा समझाएंगे?

जहां तक हिंदुत्व संविधानवाद का सवाल है, यह एक राजनीतिक अवधारणा है। इसका इस्तेमाल मैंने हिंदूनवादी राजनीति और उसके संविधान के प्रति रुझान को समझने के लिए किया है। यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि संविधानवाद के मूल रूप से दो अर्थ होते हैं। अपने पहले अर्थ में संविधानवाद राज्य और नागरिकों के आपसी रिश्तों को तय करने वाली अवधारणा है। लेकिन संविधानवाद का एक राजनीतिक अर्थ भी है। सभी राजनीतिक दल भारत के संविधान को अपने नजरिए से परिभाषित करते हैं। BJP ने भी लगभग ऐसा ही किया है। BJP का संविधानवाद इस बात पर जोर देता है कि

> मुसलमान के सवाल देश के सवाल हैं और देश के सवाल मुसलमान के सवाल हैं। भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ मुसलमान को न्याय मिलना है और मुसलमान को न्याय मिलने का अर्थ भारत के स्वधर्म की राजनीतिक अभिव्यक्ति है। इस विशिष्ट स्वधर्म को राजनीति में एक अवधारणा के रूप में लाने की सख्त जरूरत है

हम संविधान के उसूलों और उसमें वर्णित नियमों, कानूनों और उपनियमों में फर्क करें। यह संविधानवाद स्वतंत्रता समानता और सामाजिक न्याय जैसे उसूलों पर बात नहीं करता, बल्कि संविधान को कानून की पवित्र किताब बता कर नागरिकों को उसके प्रति कर्तव्य परायण होने के लिए प्रेरित करता है। संविधान की यह व्याख्या 'नए भारत' के विचार से निकलती है। मेरी किताब हिंदुत्व संविधानवाद के विशेष संदर्भ में मुस्लिम राजनीति को समझने की कोशिश है।

■ आपकी किताब का अंत फिल्म 'गर्म हवा' के एक दृश्य से होता है। इसके पीछे आपका क्या तर्क है?

मेरा मानना है कि राजनीतिक वर्ग और बौद्धिक वर्ग ने अच्छे भविष्य का सपना देखना छोड़ दिया है। हम कहीं ना कहीं वर्तमानीनष्ठि हो गए हैं। भविष्य की बात करने वाले लोगों को महज लफ्फाजी करने वाला माना जाने लगा है। योगेंद्र यादव ने पिछले कुछ वर्षों में एक नई अवधारणा का प्रतिपादन किया है जिसे वह भारत का स्वधर्म कहते हैं। उनका मत है कि पश्चिमी राजनीतिक विचार जैसे लोकतंत्र, विविधता और विकास भारतीय संदर्भ में नए सिरे से परिभाषित हुए हैं। भारत के इस विशिष्ट स्वधर्म को राजनीति में एक अवधारणा के रूप में लाने की सख्त जरूरत है। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम विविधता, विकास और लोकतंत्र तीनों को जोड़कर देखें और इस बात का विश्लेषण करें कि भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए भारत का स्वधर्म क्या है। इसी संदर्भ को लेते हुए मैंने अपनी किताब का अंत गर्म हवा फिल्म के उस दृश्य से किया है जब सिकंदर मिर्जा (जिसकी भूमिका फारुख शेख ने निभाई है), पाकिस्तान जाने के बजाय बेरोजगारी के लिए संघर्ष कर रहे नौजवानों की रैली में शामिल हो जाता है। प्रतीकात्मक रूप से यह दृश्य हमें बताता है कि मुसलमान के सवाल देश के सवाल हैं और देश के सवाल मुसलमान के सवाल हैं। भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ मुसलमान को न्याय मिलना है और मुसलमान को न्याय मिलने का अर्थ भारत के स्वधर्म की राजनीतिक अभिव्यक्ति है।

रीडर्स मेल

▶ कब आएगी जागरूकता

19 जुलाई का संपादकीय 'परदे के पीछे का सच' पढ़ा। नाबालिग बालिकाओं की शादी को लेकर नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। हमारे देश में हर साल सोलह लाख नाबालिग लड़कियों की शादी हो रही है। हालांकि 1929 में ही नाबालिग शादियों को प्रतिबंधित किया जा चुका है, इसके बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पाया है। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून तो बन गया है, पर संबंधित एजेंसियां नियमित मॉनिटरिंग नहीं कर रही हैं। इसके लिए शिक्षा की कमी भी कारण है। आज भी गरीबी के कारण अधिक उम्र के लड़के से नाबालिग लड़कियों की शादी करा दी जाती है। खासकर दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में आज भी जागरूकता नहीं आई है। कम उम्र में शादी हो जाने से इन बच्चियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

▶ असुरक्षित रेल यात्रा

यूपी के गोंडा के पास चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की पांच बोगियां पटरी से उतरकर पलट गईं। इस दुर्घटना में तीन यात्रियों की मृत्यु और कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। कुछ ही महीने पहले कई ट्रेन एक्सिडेंट हुए, जिनमें जान-माल का काफी नुकसान हुआ। मानव भूल हो या रखरखाव में कमी, लेकिन लगता यही है कि व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर कहां से लापरवाही होती है, इसका पता नहीं लगना भी चिंताजनक बात है। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में रेलवे को सतर्कता बरतते हुए उसके उपाय करने चाहिए। इसके अलावा बोगियों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। नई-नई ट्रेनें नए कलेवर में आती हैं, पर आज भी बिना सुविधा वाली बोगियों में लोग सफर करने को मजबूर हैं। बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं होता। रेलवे को यात्रियों की सुखद और सुरक्षित यात्रा को गंभीरता से लेना होगा।

शकुंतला, इंमेल से

आर.एन.आई. नं. 2120/57 संपादकीय सूचनाएं। विविध अनुरोधों के लिए संपर्क नं. आफिस पुलकेशन पुणे संपादक। नवभारतीयाई मेरा, बोरीवली गाव बलराम पेठेजेट के निए राजीव चावल द्वारा, 2 बालुडाबा नगर पार्क, नई दिल्ली-110032 से प्रकाशित तथा **राइजर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस,** मयूर 2ए, **ओखिनिल प्रेस मल्टिमाध्यम** और पार्क नंबर 2-ई, सेक्टर 16-ए, इंडस्ट्रीज़ एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, कांगड़ा, हिमाचल के मुद्रित। फोन : 2330202 फैक्स : 2340024। पंजीकृत कार्यालय : टाइम्स पंजीकृत बिल्डिंग, सूर्यो-400001। निवास पेज सूचना : 1 और आपके लिखने में कुछ मुद्दा : संपादक के पत्रकार : नवभारत 1 ए, पंजीकृत : नवभारत 2 ए, जेवाइट (टिप्पणी कार्यालय) : अशोक पोर

कर्नाटक सरकार

विवादास्पद विधेयक

कर्नाटक सरकार के विवादास्पद विधेयक में स्थानीय लोगों को 'आरक्षण' का प्राविधान किया गया था, लेकिन आईटी उद्योग की कठोर प्रतिक्रिया के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कर्नाटक सरकार को निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले विधेयक को उद्योग जगत से तीखी प्रतिक्रिया के बाद रोकना पड़ा है। सरकार राज्य विधानसभा में रखने के पहले इस पर पुनर्विचार करेगी। यह निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा विधेयक स्वीकार करने के कुछ ही घंटे के भीतर आया जिसमें निजी क्षेत्र में प्रबंधन के पदों पर 50 प्रतिशत तथा गैर-प्रबंधन पदों पर 75 प्रतिशत कन्नड़वासियों को आरक्षण का प्राविधान था। कर्नाटक 'स्टेट इम्प्लायमेंट आफ लोकल कैंडीडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर स्टैब्लिशमेंट बिल, 2024' को विधानसभा में गुरुवार को रखा जाना था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तथा उनके मंत्रियों ने विधेयक की प्रशंसा करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि यह उनके 'कर्नाटक समर्थक' दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य 'कन्नड़वासियों का कल्याण सुनिश्चित करना' है। लेकिन विधेयक का आईटी उद्योग की ओर से भारी विरोध हुआ और उसने इसकी आलोचना की। उसका तर्क था कि इससे बैंगलुरू में टेक्नोलोजी क्षेत्र प्रभावित होगा तथा कर्नाटक में आईटी उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विधेयक के पीछे राज्य के निवासियों में भारी बेरोजगारी को कारण बताया गया था। इसका उद्देश्य कर्नाटक में रोजगार के अवसरों में स्थानीय प्रतिभा को प्राथमिकता देना था।

लेकिन उद्योगपतियों का मानना था कि स्थानीय लोगों के लिए

'आरक्षण' की व्यवस्था से कंपनियों को उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा को नौकरी देने में बाधा आएगी जिससे उनकी प्रतियोगिता क्षमता तथा उत्पादकता पर विपरीत असर पड़ सकता है। वैसे भी इस विधेयक के क्रियान्वयन में विधिक व संवैधानिक मुद्दे सामने आते। यह विधेयक समानता और स्वतंत्र आवागमन का अधिकार बाधित करता जिनको भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस कारण इसके सामने अदालती बाधाएं आतीं और कानूनी दांवपेंच लंबे समय तक चलते। इसके साथ ही प्रस्तावित विधेयक से क्षेत्रवाद और सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका थी। आशंका थी कि ऐसी नीति से स्थानीय व गैर-स्थानीय के बीच विभाजन पैदा होगा। इससे समाज में विघटन तथा संभवतः टकराव पैदा हो सकता है। फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स-फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में कुल बेरोजगारी दर 2.7 प्रतिशत है जो 4.2 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन इन आंकड़ों से स्थानीय लोगों की कम रोजगार प्राप्त करने की क्षमता छिप जाती है। लेकिन इसे ठीक करने के लिए लोकरंजक उपाय सर्वोत्तम समाधान नहीं हैं। नौकरियों में आरक्षण को अनिवार्य बनाने के बजाय सरकार को स्थानीय लोगों में शिक्षा और कौशल बढ़ाने पर केन्द्रित विकास कार्यक्रम चलाने चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा बेहतरीन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से स्थानीय नौजवानों का सशक्तीकरण होगा तथा वे रोजगार बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतियोगिता कर सकेंगे। हालांकि, वापस लिया विधेयक अलग स्वरूप में वापस लाया जा सकता है। विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने के गंभीर राजनीतिक प्रभाव होंगे। कर्नाटक सरकार ने फिलहाल आईटी उद्योग व अन्य बिजनेसों से टकराव बचा लिया है, पर रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा करने वाला उसका वोटबैंक प्रभावित हो सकता है।

अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा

डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला देश में उथलपुथल वाला राजनीतिक परिवेश रेखांकित करता है। यह अमेरिकन लोकतंत्र और समाज के लिए चिन्तादायक है।

नीलांत इलांगमुवा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्या संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इस वर्ष के प्रारम्भ में आई एलेक्स गारलैंड की हालिया फिल्म 'सिविल वार' टकराव का एक काल्पनिक लेकिन भयावह परिदृश्य प्रदर्शित करती है। इससे हालिया दशकों में अमेरिका द्वारा शुरू किए युद्धों के परिणाम सामने आते हैं जिनका लक्ष्य अपना वर्चस्व स्थापित करना था, लेकिन अब देश में इसके अशुभ संकेत दिख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंनसिलवानिया के बटलर में आयोजित रैली में हत्या का प्रयास एक खतरनाक मुद्दा सामने लाता है। इस घटना के कारण अनेक कथित षडयंत्रों की चर्चा हो रही है जिनसे सीक्रेट एजेंसियों के कामकाज पर सवाल उठता है, जिनके प्रमुखों ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की आलोचना की थी। एक पुलिस स्नाइपर ने शूटर थामस मैथ्यू क्रूक्स की फोटो लगभग आधे घंटे पहले खींची थी, जब इस 20 वर्षीय युवा ने ट्रंप पर रैली के दौरान गोली चलाई। इससे हत्या का यह प्रयास रोकने की अनेक विफलतायें सामने आती हैं। इस हमले के बावजूद ट्रंप का राजनीतिक कद मजबूत हुआ है।

उन्होंने रिपब्लिकन सिनेटर जेडी वांस को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपना सहयोगी चुना है। वांस एक समय ट्रंप के मुखर आलोचक थे, पर अब वे उनके मजबूत समर्थक बन गए हैं तथा उनकी व उनकी नीतियों की मजबूत पैरोकारी कर रहे हैं। ट्रंप का कान छूती निकली गोली के बाद ट्रंप का राजनीतिक विमर्श बदल गया है और घायल होने के बावजूद वे और मजबूत हुए हैं। हालांकि, यह आश्चर्यजनक हमला अमेरिका में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक हिंसा के इतिहास का नवीनतम प्रकरण है। यह परिघटना अमेरिका के राष्ट्र बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या सबसे पहले हुई थी जिनको 1865 में जान विल्किस बूथ ने गोली मारी थी। गृह युद्ध में लिंकन द्वारा 'अश्वेत अधिकारों' के समर्थन का परिणाम उनकी 'मुक्ति घोषणा' के रूप में सामने आया था और यही उनकी हत्या के पीछे प्रमुख कारण था। इसके बाद राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड, विलियम मैक्किनले और जान. एफ कैनेडी भी ऐसी हिंसा का शिकार हुए थे। गारफील्ड की हत्या 1881, मैक्किनले की 1901 व कैनेडी की 1968 में हुई थी।

इनमें से प्रत्येक हत्या ने देश और उसकी राजनीतिक संरचना पर व्यापक प्रभाव डाला था। राजनीतिक हिंसा केवल राष्ट्रपतियों तक सीमित नहीं थी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में राबर्ट एफ. कैनेडी व जार्ज सी. वैलेस पर भी निशाना लगाया गया था। कैनेडी की 1968 में हिंसा के साथ ही बैलेस 1972 में लकवे का शिकार हुए थे। जेराल्ड फोर्ड व रोनाल्ड रीगन जैसे राष्ट्रपतियों को कई बार हत्या के प्रयासों का सामना करना पडा था। इससे अमेरिकन राजनीति में हिंसा की धमकी स्पष्ट होती है। अमेरिका आजकल इस तथ्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बन गया है कि जब नीति निर्माता बाहरी मामलों पर ज्यादा ध्यान देते हुए आंतरिक मुद्दों की अनदेखी करते हैं तो राज्य का ढांचा कमजोर हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'फेंटानिल संकट' अमेरिकी समुदायों को प्रभावित कर रहा है और इके चलते छोटे बच्चे और शिशु लगातार इस 'ओपायड' का शिकार होते जा रहे हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हेरोइन से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। देश में पैदा हुआ यह आंतरिक संकट यूक्रेन और इसराइल को गोला बारूद व उत्कृष्ट हथियारों के निर्यात से नहीं रोका जा सकता है। ऐसे समाजों में समस्याओं का मुख्यकारण केवल संस्थान न होकर प्रमुख मूल्यों का क्षरण भी होता है। एक समग्र व व्यापक मूल्य व्यवस्था के अभाव में राजनीतिक प्रबंधन बहुत कठिन हो जाता है। यह द्वंद्व ऐसे समय पैदा होता है जब प्रगति से नए मूल्यों की मांग पैदा होती है, जबकि प्रमुख मूल्य बनाए रखना स्थायित्व व सद्भावना के लिए जरूरी होता है। इस संतुलन की अनदेखी करने से समाज में अराजकता तथा नैतिक संकट की स्थिति पैदा होती है। डूबते सूरज की तरह इस अपरिहार्य क्षरण को केवल शक्ति से नहीं रोका जा सकता है।

अमेरिका में पैदा राजनीतिक परिवेश उसकी वैश्विक कार्यवाइयों का परिणाम है और अनेक अभूतपूर्व घटनाओं के माध्यम से यह अवश्यंभावी पतन का संकेत देता है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से जारी उन नीतियों का उत्पाद हैं जो अक्सर घरेलू प्रभावों की अनदेखी से पैदा होते हैं। वे अमेरिकन राजनीति में कारणों के बजाय एक लक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अमेरिकन जनता की कीमत पर दूसरे देशों का शोषण करने के इतिहास से सामने आया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजनीतिक हिंसा में शामिल होना एक विकृत गतिविधि है जिसके नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। किसी का जीवन छीनना नैतिक रूप से पूर्णतः गलत है, भले ही उसकी भूमिका तथा गलतियां चाहे जो हों। ट्रंप की हत्या का प्रयास अनेक सवाल खड़े करता है जिनके जवाब नहीं दिए गए हैं। इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि 'गनशाट डिटेक्टर्स' का रैली में प्रयोग किया गया था, जबकि ऐसे डिटेक्टर तेजी से शूटर का पता लगा सकते हैं। शूटर थामस क्रूक्स ने ऐसी बंदूक का प्रयोग किया जिसे विधिक रूप से उसके पिता ने विधिक रूप से खरीदा था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या बंदूक खासतौर से उसके लिए खरीदी गई थी क्योंकि पेंसिलवानिया के कानून 20 वर्षीय लोगों को बंदूक खरीदने का अधिकार देते हैं।

खबरों के अनुसार शूटर की पहचान उसके डीएनए से हुई, इसका अर्थ है कि परिवारी सदस्यों ने नमूने दिए थे। खबरों से यह भी पता चलता है कि बंदूक का सीरियल नंबर छिपाने के कोई प्रयास नहीं किए गए थे और शूटर ने हाल ही में 50 राउंड 5.56 एमएम गोलियां खरीदी थीं। प्राथमिक एकास्टिक प्रमाणों से संकेत मिलता है कि ट्रंप पर निशाना लगाने में अनेक शूटरों का प्रयोग किया गया था। खबरों के अनुसार, शुरुआती गोली शूटर की स्थिति से चलाई गई थी, जबकि बाद में अज्ञात स्रोतों से भी गोलियां चलाई गईं। सीक्रेट सर्विस इसपर्दा द्वारा खतरे को समाप्त करने के लिए एक गोली चलाई गई, जबकि एकास्टिक प्रमाणों से इसमें असंगति दिखाई देती है। इससे घटना की और गंभीरता से जांच की आवश्यकता उजागर होती है। एक बीस वर्षीय युवा द्वारा तोड़ी गई सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं जिसके चलते वह ट्रंप की रैली के निकट एक छत तक पहुंच गया और उसने अनेक गोलियां चलाईं। प्रमुख शूटर के तौर पर थामस मैथ्यू क्रूक्स की पहचान की गई है, लेकिन एक संभावित दूसरे शूटर का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि क्रूक्स एक अकेला व्यक्ति था और सोशल मीडिया पर उसकी कोई उपस्थिति नहीं थी। ऐसे में उसकी अप्रत्याशित भूमिका तथा उसके वाहन में बरामद हुए विस्फोटकों से घटना की और विस्तृत जांच की आवश्यकता उजागर होती है। रैली की सुरक्षा की आलोचना में खासकर बिल्डिंगों की अनुपयुक्त कवरेज पर ध्यान दिया जा रहा है जिसे शूटर को सीधे ट्रंप को देखने का मौका मिला। यह गंभीर सुरक्षा विफलता का उदाहरण है। ये कमियां सुरक्षा प्रोटोकालों में गंभीर गड़बड़ियों का संकेत देती हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता उजागर होती है।

इसके साथ ही यह कहना भी जरूरी है कि राजनीतिक हिंसा से विरले ही उन मुद्दों का समाधान होता है जिनके समाधान की आशा इससे की जाती है। ऐतिहासिक रूप से ऐसी हिंसा से केवल विभीषिका के दुष्चक्र पैदा होते हैं और वे उन लक्ष्यों को नुकसान हीं पहुंचाते हैं जिनको हिंसा के पैरोकार प्राप्त करना चाहते हैं। अमेरिकन संस्कृति में फैल रही आक्रामकता ने अमेरिका की संस्कृति और आध्यात्मिक विकास को घातक रूप से धक्का दिया है। इससे स्वयं लोकतंत्र को भारी नुकसान होता है। लोकतंत्र जहां लोगों को परंपरागत बाधाओं से मुक्ति दिलाता है वहीं यह आत्म-नियंत्रण व आत्म-मूल्यांकन की आवश्यकता भी उजागर करता है। विडंबना है कि परंपरागत पश्चिमी मूल्यों के क्षरण के कारण इसमें भारी बाधा आई है। सामाजिक मूल्य व्यवस्था की वास्तविक निर्देशक शक्ति के बिना किसी देश की राज्य संरचना अपरिहार्य रूप से विफल हो जाती है, जबकि यह व्यक्तियों के निर्णय तय करने में महत्वपूर्ण होती है। सामूहिक विचारों के ध्वस्त होने का सामाजिक संस्थानों व व्यवहारों से निकट संबंध है।

ट्रंप पर जानलेवा हमला अमेरिका में उन नीतियों की समीक्षा का अवसर देता है जो लफ्फाजी के साथ ही राजनीतिक हिंसा को सामान्य बना रही हैं।

सूचनाधिकार कानून के समक्ष चुनौतियां

> नई सरकार के गठन के बावजूद, रिक्तियां अभी भी खाली हैं, जिससे देरी बढ़ रही है और बचे हुए कुछ आयुक्तों पर बोझ बढ़ रहा है।

प्रियदर्शी दत्ता
(लेखक, स्वतंत्र शोधकर्ता हैं)

पिछले साल 13 सितंबर को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत इस स्तंभकार की दूसरी अपील स्वीकार की थी। अपील में सूचना देने से इनकार करने के लिए सीपीआईओ पर जुर्माना लगाने के अलावा अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कुछ प्रासंगिक सुझाव भी शामिल थे। हालांकि, 6 नवंबर को उस विशेष मंत्रालय के मामलों को देखने वाली सूचना आयुक्त सुश्री सरोज पुन्हानी अपने कार्यकाल के अंत में सेवानिवृत्त हो गईं। उसी दिन एक अन्य सूचना आयुक्त उदय माहुरकर सेवानिवृत्त हुए, जबकि उनके सहयोगी सुरेश चंद्र दो दिन पहले सेवानिवृत्त हुए थे। सुश्री वंजना एन. सरना, नीरज कुमार गुप्ता और डॉ. अमिता पांडोव जैसे कई अन्य सूचना आयुक्त पिछले साल की शुरुआत में अपने-अपने कार्यकाल के अंत में सेवानिवृत्त हो गए थे। मुख्य सूचना आयुक्त वाई. के. सिन्हा 3 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2023 के अंत तक आयोग की कुल संख्या घटकर मात्र तीन रह गई, जबकि वर्ष की शुरुआत में अधिकतम दस सदस्य थे। पिछले महीने नई सरकार के गठन के बाद भी रिक्त पदों को भरने में बहुत कम रुचि दिखाई गई है।

आयोग की संख्या में कमी के कारण सीआईसी भवन में दूसरी अपीलों और शिकायतों का बोझ बढ़ गया है। इस स्तंभकार की दूसरी अपील, जो पहले से ही दस महीने से लंबित है, में अनिश्चितकालीन प्रतीक्षा अवधि देखने को मिल सकती है। इसके परिणाम की तुलना न्यायपालिका में लंबे इंतजार से नहीं की जा सकती। सूचना नाजुक होती है और न्याय से भी तेजी से पुरानी हो जाती है। यहीं पर इस स्तंभकार के सुझाव मददगार साबित हो सकते थे। 2010 से आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपने सीमित अनुभव में उन्होंने पाया है कि सीपीआईओ (केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी) आम तौर पर सूचना को कर्तव्यनिष्ठा से साझा करते हैं। हालांकि, जहाँ वे ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी, जो आम तौर पर विभाग/मंत्रालय में उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, बहुत कम मदद करते हैं। वे अपने कनिष्ठों के साथ मिलकर सूचना को दबाते हैं, जाहिर तौर पर कार्यालय की राजनीति में एहसान/दायित्वों के बदले में।

सूचना आयुक्त के रूप में उदय माहुरकर ने कथित तौर पर 2021-22 में 5056 आरटीआई अपीलों का निपटारा किया, जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के वर्ष के बाद से सबसे अधिक है। हालाँकि, यह अपीलीय प्राधिकारी के पूर्ण गैर-निष्पादन का भी प्रतिबिंब है। यदि उन मामलों का विभाग के भीतर ही पहली अपील के चरण में संतोषजनक ढंग से निपटारा कर दिया गया होता, तो दूसरी अपील के लिए सीआईसी से संपर्क करने की बहुत कम आवश्यकता होती। कई कारणों से सूचना को दबाया जा सकता है। दुर्लभ मामलों में, ऐसा हो सकता है कि सीपीआईओ ने अपनी मूल क्षमता (अनुभाग अधिकारी या अवर सचिव के रूप में) में कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसकी वह जांच करवाना चाहता हो। इस मामले में, एक व्यक्ति को झूठे आरोपों के आधार पर काली सूची में डाल दिया गया, जबकि उसका मंत्रालय के साथ कोई वित्तीय लेन-देन नहीं था।

काली सूची में डालने के आदेश पर, हालांकि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, सीपीआईओ ने अवर सचिव के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता में हस्ताक्षर किए थे। जब उनसे फाइल नोट्स, यदि कोई शिकायत हो, नियमों का उल्लंघन हो, आदि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर मामले को टाल दिया कि फाइल प्रस्तुत की जा रही है (आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देने से इनकार करने का ऐसा कोई आधार नहीं है, भले ही फाइल पीएमओ या राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुत की गई हो)। इस स्तंभकार ने एक साल बीत जाने के बाद (सीआईसी में महीनों से लंबित अपील के कारण) वही जानकारी मांगी, तो पाया कि फाइल अभी भी प्रस्तुत की जा रही है!

निष्कर्ष स्पष्ट हैं। दोनों ही अवसरों पर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, जो एक आईएएस अधिकारी है, ने पारदर्शिता के बजाय दमन के कारण को बढ़ावा दिया। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत आवेदक को सूचना देने से अनुचित तरीके से इनकार करने पर सीपीआईओ पर 25,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

हालांकि, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य में स्पष्ट रूप से विफल रहने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। अनुशासनात्मक कार्यवाही की किसी गुंजाइश के बगैर कार्यपालिका के किसी सदस्य को अर्ध-न्यायिक शक्ति प्रदान करना शक्ति के दुरुपयोग का ही एक तरीका है। अपील की सुनवाई के लिए सीआईसी नोटिस केवल सीपीआईओ को भेजा जाता है, न कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को। सीपीआईओ, जो एक जूनियर अधिकारी है, के सामने सूचना आयुक्त द्वारा डांट दिए जाने का डर प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से कार्रवाई की ईमानदारी सुनिश्चित करेगा।

प्रथम अपीलीय अधिकारी को अनुशासित करना केंद्रीय सूचना आयोग के डेस्क पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने की कुंजी है। सरकार ने हाल ही में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की याद में एक अजीब नाम है।

जबकि आपातकाल लोकतंत्र विरोधी हो सकता था, यह अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होने के कारण अपने आप में असंवैधानिक नहीं था। अगर सरकार 21वीं सदी में लोकतंत्र को मजबूत करने में दिलचस्पी रखती है तो संविधान हत्या दिवस या यहां तक कि भारत लोकतंत्र की जननी जैसी बयानबाजी काम नहीं करेगी अगर सीआईसी की तादात कम कर दी जाए। 2005 का आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन के लिए एक प्रमुख उपकरण था।

आप की बात

पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना अनेक प्रकार से लाभप्रद सिद्ध होगा। वर्तमान कर व्यवस्था में उत्पादन के प्रत्येक चरण पर केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे करारोपण व राज्यों द्वारा अधिकाधिक वैट लगाने के कारण देश में डीजल व पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी होती है। इनके ऊंचे दामो से वस्तु परिवहन एवं माल भाडे की लागत बढ़ जाती है जो खाद्यान्न सहित अनेक वस्तुओं की महंगाई बढ़ने का कारण है। पेट्रोलियम उत्पदों को जीएसटी के दायरे में लाने से देश भर में इनकी मानक दरें तय होगी तथा कीमतों में एकरुपता आएगी। इससे जीएसटी का मूल उद्देश्य-एक राष्ट्र एक बाजार एक कर पूरा होगा। इससे राज्यों के बीच पैट्रोलियम उत्पादों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी, ढुलाई की लागत घटेगी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार आएगा। शराब के बाद पेट्रोलियम उत्पादो पर कर राज्यो की राजस्व आय का प्रमुख साधन है। इसीलिए कोई भी राज्य इस पर वैट लगाने का अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन केंद्र द्वारा राज्यो के बीच आम-सहमति बनाने एवं पेट्रोलिमय उत्पादों पर जीएसटी से प्राप्त कर राजस्व के अलग से वितरण के प्रस्ताव द्वारा उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू करने के लिए राजी किया जा सकता है।

– **विमलेश पगारिया,** बदनावर

बाल विवाह

सिविल सोसाइटी संगठनों के नेटवर्क चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया से जुड़ी रिसर्च टीम इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने 2011 की जनगणना से आंकड़ों के साथ एनसीआरबी और नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की सूचनाओं का विश्लेषण किया। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 16 लाख नाबालिग लड़कियों की शादी हो रही है। हालांकि, भारत में आजादी से पूर्व 1929 में ही नाबालिगों की शादी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब प्रशासकीय अमले के साथ-साथ सुदूर गांवों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता तैनात हैं। इसके बावजूद नाबालिग लड़कियों की शादी प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं। संचार क्रांति के चलते गांव-गांव तक स्मार्टफोन और टीवी के जरिए हर नागरिक को पता है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध होने के साथ-साथ नाबालिग बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करता है। बाल विवाह रोकने के लिए तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देश की व्यापक प्रगति के बावजूद सबसे गरीब लोगों में सामाजिक जागरूकता तथा शिक्षा का अभाव एवं सड़ी-गली पुरानी मान्यताओं का अब भी बना रहना बाल विवाह का मुख्य कारण है।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

तलाक की विभीषिका

तलाक खासकर बच्चों के लिए हृदयविदारक है जिससे उनका भविष्य चौपट हो सकता है। उन्हें असल माता-पिता का लाड़-दुलार जो एक घर में रह कर मिलता है वह माता पिता के दूर-दूर रहकर नहीं मिल सकता है। यदि बच्चे से माँ या पिता दूर रहे तो वह एक के प्यार से वंचित ही रहेगा। यदा-कदा बच्चे से मिलना और पेरेंट्स के साथ बारी-बारी से बच्चे के रहने से सामान्य जीवन की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। बेहतर यही है कि या तो युगल शादी बहुत ही सोच समझ कर करें। विवाह बंधन में बंधने और बच्चा पैदा होने के पश्चात यदि कोई विवाद हो तो उसे बच्चे के सामने आने वाली कठिनाइयों को देख कर हल करने का प्रयास करें। युवाओं को समझना चाहिए कि तलाक एक मामूली सा सम्बन्ध विच्छेद नहीं है, बल्कि इससे पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। विडंबना है कि भारत में संयुक्त परिवार टूटने तथा एकल परिवारों में भी माता पिता के अलग-अलग स्थानों में काम करने अथवा अपने साथी की सोच से समझौता न करने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण तलाक जैसी कुप्रथा बढ़ती जा रही है। इस विभीषिका का सबसे हानिकारक प्रभाव बच्चों के साथ उन वृद्धों पर भी पड़ता है जो अपने युवा बेटे-बेटियों से दूर रहने पर मजबूर होते हैं।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

कांवड़ यात्रियों को सुविधा

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा, दुकानों या ठेलों पर मालिक का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर सियासी घमासान मचा है। जबकि मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश में कोई बुराई नहीं है। नाम प्रदर्शित होने से शुद्ध शाकाहारी कांवड़ियों को सुविधा मिलेगी जो कम से कम इस यात्रा के दौरान लहसुन, प्याज जैसी चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। कई बार शुद्ध शाकाहारी लोग जाने अनजाने नाम के भ्रम में ऐसी दुकानों पर चले जाते हैं, जहां वेज व नानवेज दोनों प्रकार का भोजन बनता है। अतीत में ऐसे अनेक मामले विवाद का कारण बने हैं। विपक्षी दलों को ऐसे मुद्दों पर सियासत करने से बचना चाहिए। यह सियासत का मसला है ही नहीं। किसी भी ग्राहक को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी दूकान से सामान खरीदे या नहीं। समस्या कुछ लोगों द्वारा अपनी पहचान छिपा कर फर्जी नाम से मुनाफा बटोरने के कारण पैदा होती है। दूकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित होने से खाद्य वस्तुओं में मिलावट अथवा अन्य कारणों से किसी के बीमार होने पर पुलिस व प्रशासन को दोषी दूकानदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुविधा होगी।

– **हेमा हरि उपाध्याय,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

किसी समस्या का समाधान उसी विचार प्रक्रिया से नहीं कर सकते, जिससे वह पैदा हुई हो। -अल्बर्ट आइंस्टीन

बारिश ने भीषण हीटवेव से तो राहत दिलाई है, लेकिन इसकी असामान्य प्रकृति से उत्तर भारत समेत पूरे देश में पैदा हो रही बाढ़ और भू-स्खलन की स्थितियां हर साल की भांति इस बार भी पूर्व तैयारियों पर सवाल उठाती दिख रही हैं।

बारिश और सवाल

भीषण हीटवेव वाले महीनों से जूझने के बाद अब बारिश ने गर्मी से निजात तो दिलाई है, लेकिन इसकी असामान्य प्रकृति ने उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के लिए कई अन्य मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। असम में बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, तो उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश अपना कहर दिखा रही है। गुजरात और कर्नाटक के कई शहर पानी-पानी हो रहे हैं, तो केरल में भी प्रकृति का रौद्र रूप देख स्कूल-कॉलेज बंद करने की घोषणा हुई है। तमिलनाडु के नीलगिरि में भारी बारिश और भू-स्खलन की खबरें मिल रही हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी मौसम विभाग अलर्ट जारी कर चुका है। बारिश ने दिल्लीवासियों को कुछ राहत दी है, तो वायु की गुणवत्ता भी सुधारी है। लेकिन जल जमाव के कारण सड़कें और पार्क तो तालाब बने ही हैं, कई अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या विकराल हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां पिछले करीब एक हफ्ते से बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वाराणसी में गंगा के ज्यादातर घाट डूब चुके हैं। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अल नीनो के तटस्थ चरण में लौटने से इस मानसून में देश में भारी बारिश हो रही है। इसके उत्तरार्ध अगस्त व सितंबर में ठंडे ला नीना चरण बनने की उम्मीद है, जो हर तीन से पांच साल में होता है और जिसके परिणामस्वरूप समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है। इससे सर्वाधिक वर्षा की आशंका तो है ही, मौसम के अलग-अलग पैटर्न बनने से बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। हालांकि भारत में बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है और खासकर मानसून के दौरान देश के कई हिस्से हर साल इसका सामना करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना जैसी

प्रमुख नदियां भारी बारिश के दौरान अपने किनारों को पार कर जाती हैं, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन असामान्य बारिश के पीछे जलवायु परिवर्तन के अलावा, नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास और वनों की कटाई जैसे कारक भी हैं, जो बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वन संरक्षण, जल संचयन और स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाना तो जरूरी है ही, बाढ़ प्रबंधन की दीर्घकालिक योजनाएं बनाना और शहरों में जल निकासी प्रणालियों को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है।

एआई से निगरानी की कीमत चुकानी होगी

26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक की एआई द्वारा निगरानी फ्रांसीसी सरकार और एआई कंपनियों के लिए बेशक लाभकारी हो, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी होगी। खराब ढंग से विनियमित एआई-सक्षम निगरानी प्रणालियों में गोपनीयता उल्लंघन की आशंका रहती ही है।

पेरिस ओलंपिक पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि हजारों एथलीट एवं उनके सहयोगी कर्मचारी और दुनिया भर से लाखों पर्यटक फ्रांस पहुंचने लगे हैं। इस पर सिर्फ दुनिया की ही नजर नहीं होगी, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली (एआई सिस्टम) से भी इसकी निगरानी की जाएगी। सरकार और निजी कंपनियां खेलों से पहले, खेलों के दौरान और खेलों के बाद उन्नत एआई उपकरणों एवं अन्य निगरानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगी। ओलंपिक के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की भीड़ के कारण सुरक्षा जोखिम इतना बढ़ जाता है कि अधिकारियों और आलोचकों ने इसे 'युद्ध से अलग दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन' बताया है।

ऐनी हूमी मेककेना
रिचमंड विश्वविद्यालय में विधि की विजिटिंग प्रोफेसर

फ्रांस की सरकार ने निजी प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ मिलकर सुरक्षा बढ़ाने की वैध जरूरत के मद्देनजर निगरानी और डाटा एकत्र करने वाले उन्नत तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया है। प्रायोगिक एआई वीडियो निगरानी के विवादास्पद इस्तेमाल समेत इसकी निगरानी योजनाएं इतनी व्यापक हैं कि उन्हें वैध बनाने के लिए कानून में बदलाव करना पड़ा है। खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक अनंतिम आदेश जारी किया है, जो सरकार को खेलों के दौरान पारंपरिक, गुप्त निगरानी और सूचना एकत्र करने के साधनों को बढ़ाने की अनुमति देता है।

सुरक्षा जोखिम बढ़ने के साथ-साथ निगरानी बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है और बढ़ाई भी जाती है। हालांकि निवारक उपाय जोखिमों के अनुपात में ही होने चाहिए। दुनिया भर के आलोचकों का दावा है कि फ्रांस निगरानी पर पकड़ बढ़ाने के लिए ओलंपिक को बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है और सरकार इस 'असाधारण' निगरानी का इस्तेमाल समाज पर राज्य की निगरानी बढ़ाने के लिए करेगी।

इसके साथ ही, सुरक्षा के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी निगरानी को लेकर भी वाजिब चिंताएं हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में यह सवाल उठ रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास को रोकने में सीक्रेट सर्विस

की सुरक्षा निगरानी क्यों चूक गई। नए विस्तृत निगरानी कानून के साथ फ्रांस एआई कंपनियों के साथ मिलकर व्यापक एआई वीडियो आधारित निगरानी लागू करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने महत्वपूर्ण संगीत समारोहों, खेल आयोजनों एवं मेट्रो व रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के दौरान एआई तकनीक से निगरानी की है, जिनमें टेलर स्विफ्ट का कंसर्ट एवं कान फिल्म महोत्सव भी शामिल हैं। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि एआई निगरानी के इन प्रयोगों में सफलता भविष्य में भी इनके उपयोग के लिए 'हरी झंडी' है।

एआई सॉफ्टवेयर को आम तौर पर भीड़ के आकार और गतिविधि में परिवर्तन, छोड़ी गई वस्तुओं, हथियारों की मौजूदगी या इस्तेमाल, जमीन पर शव, धुएं या लपटें और ट्रैफिक उल्लंघनों जैसी कुछ घटनाओं को चिह्नित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य निगरानी प्रणालियों के लिए रियल टाइम में गेट की ओर बढ़ती भीड़ या भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने में किसी के द्वारा बैग छोड़ने जैसी घटनाओं का पता लगाना और सुरक्षा कर्मियों को सचेत करना है। इन घटनाओं को चिह्नित करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल तार्किक और समझदारी भरा लगता है। लेकिन वास्तविक गोपनीयता और कानूनी सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं और इनका कैसे इस्तेमाल होता है। इतने डाटा को एकत्र करने के बाद क्या किया जाएगा और इस तक किसकी पहुंच होगी? इन सवालों का जवाब देने के लिए पारदर्शिता का अभाव है।

लोगों की पहचान कर सकने वाले बायोमेट्रिक डाटा के इस्तेमाल को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के बावजूद बहुत संभव है कि इसका दुरुपयोग किया जाए। निजी कंपनियों को फ्रांस में पहले से ही लगे हजारों वीडियो कैमरों तक पहुंच प्रदान करके, रेल कंपनियों और परिवहन ऑपरेटरों की निगरानी क्षमताओं का उपयोग और समन्वय करके, और कैमरों के साथ ड्रोन के उपयोग की अनुमति देकर, फ्रांस इन कंपनियों को अपने नागरिकों और आगंतुकों पर एआई सॉफ्टवेयर का परीक्षण एवं प्रशिक्षण देने की अनुमति व समर्थन दे रहा है। बीजिंग में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं इतनी ज्यादा थीं कि एफबीआई ने 'सभी एथलीटों' से आग्रह किया कि वे अपने निजी सेलफोन घर पर ही छोड़ दें और चीन में केवल प्रीपेड फोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि सरकारी निगरानी बहुत ज्यादा है।

हालांकि फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। यूरोपीय संघ का सामान्य डाटा संरक्षण विनियमन दुनिया के सबसे मजबूत डाटा गोपनीयता कानूनों में से एक है, और यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम एआई प्रौद्योगिकियों के हानिकारक इस्तेमाल को विनियमित कर रहा है। इसलिए फ्रांस को यूरोपीय संघ के कानून का पालन करना चाहिए।

ओलंपिक की तैयारी करते हुए फ्रांस ने वर्ष 2023 में कानून संख्या 2023-380 लागू किया, जिसमें विवादास्पद अनुच्छेद सात भी शामिल है, जो फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उसके तकनीकी ठेकेदारों को एआई वीडियो निगरानी के साथ प्रयोग की अनुमति देता है और अनुच्छेद दस विशेष रूप से वीडियो और कैमरा फीड की समीक्षा करने के लिए एआई सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति देता है।

विद्वानों, नागरिक समाज समूहों और नागरिक स्वतंत्रता पैरोकारों ने आरोप लगाया कि ये अनुच्छेद सामान्य डाटा संरक्षण विनियमन और एआई को विनियमित करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों के विपरीत हैं। हालांकि फ्रांसीसी अधिकारियों और तकनीकी कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा है कि एआई सॉफ्टवेयर लोगों की पहचान किए बिना संदिग्ध घटनाओं की पहचान करने के अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि बायोमेट्रिक डाटा को कैप्चर और प्रोसेस किया जा रहा है, और इस प्रकार फ्रांस का कानून जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का उल्लंघन करता है।

फ्रांसीसी सरकार और एआई कंपनियों के लिए अब तक एआई निगरानी पारस्परिक रूप से लाभकारी रही है। लेकिन इन एआई-सक्षम निगरानी प्रणालियों का विनियमन बहुत खराब तरीके से होता है। एक बार बायोमीट्रिक डाटा एकत्र हो जाने के बाद गोपनीयता उल्लंघन की आशंका रहती ही है।

(कन्वर्सेशन से)

edit@amarujala.com

जीवन धारा

रॉय टी. बेनेट

हम किसी के जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में मोमबत्ती जलाना सीखें। वह प्रकाश बनें, जो दूसरों को देखने में मदद करे। यह जीवन को ज्यादा सार्थक बनाता है और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें।

दूसरों में अच्छाई देखिए, तो जीवन सुंदर बन जाता है

हम सभी अलग-अलग हैं। इसलिए किसी को आंकें नहीं, बल्कि उन्हें समझें, और अपने सपनों का जीवन जिएं। अपना समय क्रोध, पछतावे, चिंता और दुर्भावना में बर्बाद न करें। चूंकि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए अपना समय उन लोगों पर बर्बाद मत करें, जो आपका सम्मान नहीं करते और आपको महत्व नहीं देते। खुद पर विश्वास रखें। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा बहादुर हैं। जितना जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हैं और उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। यह भी याद रखें कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। हो सकता है कि आपके लिए इसका कोई मतलब न हो, लेकिन उनके लिए इसका बहुत मतलब हो सकता है।

अपने आप को केवल तभी बदलें और बेहतर कर सकते हैं, जब आप अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखते हैं। सफलता यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, बल्कि यह है कि आप दुनिया में किस तरह सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह तभी संभव है, जब आप वह काम करते हैं, जो सही है, न कि वह, जो आसान या लोकप्रिय है। सबसे कठिन समय अक्सर आपको जीवन के सबसे बेहतरीन पलों की ओर ले जाते हैं। इसलिए चलते रहें। कठिन परिस्थितियां अंत में लोगों को मजबूत बनाती हैं। जब हम दूसरे लोगों में अच्छाई देख पाते हैं, तो जीवन अधिक आसान और सुंदर हो जाता है। इसलिए हम किसी के जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में मोमबत्ती जलाना सीखें। वह प्रकाश बनें, जो दूसरों को देखने में मदद करे। यही वह चीज है, जो जीवन को ज्यादा सार्थक बनाती है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें, इसे कभी भी दूसरे लोगों के हाथों में न सौंपें। आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसका चुनाव आप हमेशा खुद कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार और आभारी हृदय से करें। अपने दिल में यह विश्वास रखें कि आप जुनून, उद्देश्य, जादू और चमत्कारों से भरा जीवन जीने के लिए बने हैं। अपने दिल की सुनें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और दूसरे क्या सोचते हैं, इसकी परवाह करना बंद कर दें। महान चीजें उनके साथ घटित होती हैं, जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना नहीं छोड़ते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आप कल से बेहतर बन सकें और अपने आस-पास के लोगों और दुनिया की सेवा कर सकें। कोई भी व्यक्ति जीवन की परीक्षाओं से मुक्त नहीं है, लेकिन हर कोई हमेशा हर चीज में कुछ न कुछ सकारात्मक खोज सकता है, यहां तक कि सबसे बुरे समय में भी। हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसकी तब तक सराहना नहीं करते, जब तक वह खत्म नहीं हो जाता। हम किसी चीज की तब तक प्रशंसा नहीं करते, जब तक कि हम कुछ घटनाओं का अनुभव नहीं कर लेते। हम अपने माता-पिता की परेशानियां तब तक नहीं समझते, जब तक कि खुद माता-पिता नहीं बन जाते।

जो है, उसके लिए आभारी रहें

सूत्र

आपके पास अभी जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी रहें और किसी भी चीज को हल्के में न लें। आपको किसी को पसंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसे व्यवहार की अपेक्षा आप खुद के लिए चाहते हैं।

दूसरा पहलू

सर्पदंश के मामलों में भारत में कई बार इलाज में विलंब होने, तो बहुत से लोग डर के चलते घबराहट में अपनी जान गंवा देते हैं।

लोग सिर्फ सांप के जहर से नहीं मरते

धरती पर सुंदरतम जीवों में से एक सांप अपने जहर के कारण डरावना और जानलेवा बन गया है, वरना उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन हर साल सर्पदंश से सबसे ज्यादा गरीब तबका अपनी जान गंवाता है। भारत में यह आंकड़ा अत्यधिक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की बीते वर्ष की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लाखों लोग सर्पदंश का शिकार हो रहे हैं, जिनमें भारतीय सबसे ज्यादा हैं। इनमें किसान, मछुआरे, कामकाजी बच्चे, महिलाएं ज्यादातर हैं, क्योंकि गरीबी के चलते ये धरती को ही अपना बिछौना बनाकर उस पर सोते हैं, जहां रात-बिरात सांप बेखटके पहुंच जाते हैं। सोते लोगों के शरीर की हलचल से अनजाने ही अपने बचाव में सांप लोगों को डस लेते हैं।

ऋतुपर्ण दवे

भारत में प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख से 12.5 लाख सर्पदंश के मामले घटते हैं, जिसमें लगभग 58,000 लोग जान गंवाते हैं। पालतू पशुओं की मौत का कोई हिसाब ही नहीं है।

कई शोध अध्ययनों से पता चलता है कि प्रति वर्ष विश्व भर में सांप के डसने की लगभग 50 लाख से ज्यादा घटनाओं में लगभग डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि करीब चार लाख लोग स्थायी विकलांगता का सामना करते हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख से 12.5 लाख सर्पदंश के मामले घटते हैं, जिसमें लगभग 58,000 लोग जान गंवाते हैं। सर्पदंश से पालतू पशु भी मरते हैं, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। भारत में ज्यादातर मौतें डर और अज्ञानतावश होती हैं। कई बार इलाज के लिए काफी देर हो चुकी होती है, तो बहुत से लोग डर के चलते घबराहट में मर जाते हैं। बहुत से लोग झाड़-फूंक और ओझा-गुनी के चक्कर में फंसकर जान गंवा बैठते हैं। भारत में सांपों की 276 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लगभग 60 जहरीली मानी जाती हैं।

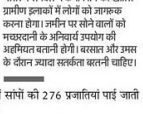

भारत में सर्पदंश में कमी लाने की खातिर ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करना होगा। जमीन पर सोने वालों को मच्छरदानी के अनिवार्य उपयोग की अहमियत बतानी होगी। बरसात और उमस के दौरान उपाय की अहमियत बतानी होगी। बरसात और उमस के दौरान जादा सतर्कता बरतनी चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन सन 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मृत्यु और विकलांगता को पचास फीसदी तक कम करने के लक्ष्य के मद्देनजर काम कर रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू में विष विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख मानते हैं कि यह गरीब आदमी की समस्या है, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत में सर्पदंश में कमी लाने की खातिर ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करना होगा। जमीन पर सोने वालों को मच्छरदानी के अनिवार्य उपयोग की अहमियत बतानी होगी। बरसात और उमस के दौरान ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। इन्हीं छोटे, किंतु महत्वपूर्ण उपायों से भारत को दुनिया के सबसे बड़े सर्पदंश पीड़ित होने के अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है।

आंकड़े

नई नौकरियां

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2023-24 में अनुमानित रोजगार वृद्धि दर छह फीसदी देखी गई, जो 2022-23 से दोगुनी है।

2019-20	5.5%
2020-21	5.1%
2021-22	3.3%
2022-23	3.2%
2023-24	6.0%

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.7 करोड़ नई भर्तियां हुईं हैं।

स्रोत : RBI

कल गुरु पूर्णिमा है। महाभारत और अठारह पुराणों के रचयिता आदि गुरु कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने देवर्षि नारद के सुझाव पर *श्रीमद्भागवत पुराण* की रचना की।

नारद ने बताया व्यास का कर्तव्य

महाभारत और अठारह पुराणों के रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसे गुरु या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। बताया जाता है कि पैदा होते ही वेदव्यास एकांतवास और तपस्या के लिए जाने लगे। मां के रोकने पर उन्होंने वचन दिया कि वह जब भी याद करेंगी, तब उपस्थित हो जाएंगे।

सत्यवती के निर्देश पर ही वेदव्यास की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर का जन्म हुआ। वेदों का विभाजन, *महाभारत* और पुराणों की रचना करने के बावजूद वेदव्यास एक दिन इस चिंता में बैठे हुए थे कि मेरा कोई कर्तव्य बाकी रह गया है। इसी बीच देवर्षि नारद उनके पास पहुंचे और उनकी चिंता का कारण पूछा। वेदव्यास ने कहा कि देवर्षि आपका आगमन बड़ा ही शुभ हुआ है। कृपा कर बताएं कि मेरा कौन-सा कर्तव्य बाकी रह गया है।

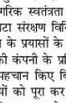

अंतर्यात्रा
संकलित

देवर्षि ने कहा कि आप सबकुछ जानते हैं, *महाभारत* में सब आ गया है। आपने अनेक महापुरुषों को उपदेश दिया है। फिर भी आपने मुझसे पूछा है, तो आप *श्रीमद्भागवत पुराण* की रचना करें। इसमें श्रीहरि का गुणगान होगा। भगवान श्रीकृष्ण का जिसमें गुणगान हो, इससे अच्छा और क्या होगा? उन्होंने *श्रीमद्भागवत* की रचना की। इसके बाद उन्होंने शुकदेव को इसका अध्ययन कराया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 02 जून, 1956

प्रत्यक्ष कर का अध्ययन करने अमेरिका-ब्रिटेन जाएगा दल

संपत्ति व मुनाफे पर शीघ्र कर लगेंगे
संपत्ति के वितरण की ओर ध्यान
वर्ष १५) मन

राज्यसभा में वित्तमंत्री देशमुख ने बताया कि धन के समुचित वितरण को लेकर भारत सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का दल प्रत्यक्ष कर पद्धति का अध्ययन करने के लिए अमेरिका व ब्रिटेन जाएगा।

अब झरने भी गिने जाएंगे

देश की 20 फीसदी आबादी झरनों पर निर्भर है। हिमालय क्षेत्र में 50 फीसदी झरने सूख रहे हैं, तो दक्षिण के बारहमासी झरने मौसमी होते जा रहे हैं।

पंकज चतुर्वेदी — पर्यावरण

भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी तरह के जल स्रोतों की दूसरी गणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले साल हुई पहली गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, जिसके आधार पर यह पता चला था कि देश में नदियों, नहरों के साथ ही कितने तालाब, पोखर, झील आदि हैं और उनकी स्थिति क्या है? इस बार की गणना की खासियत है कि इसमें झरनों को भी शामिल किया गया है।

देश की सैकड़ों गैर हिमालयी नदियां, खासकर दक्षिण राज्यों की नदियों का तो उद्गम ही झरनों से है। नर्मदा, सोन जैसी विशाल नदियां मध्य प्रदेश में अमरकंटक के झरने से ही फूटती हैं। जब दो साल बाद इस गणना के नतीजे सामने आएंगे, तो देश के पास एक व्यापक परिदृश्य होगा कि नदियों की धार का भविष्य क्या है? जल विद्युत परियोजनाओं की संभावना क्या है? झरने का अस्तित्व पहाड़ से है, उसे ताकत मिलती है परिवेश के घने जंगलों से और संरक्षण मिलता है अविरल प्रवाह से।

2020 में, अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका *'वाटर पॉलिसी'* ने भारतीय हिमालय क्षेत्र (आईएचआर) में स्थित 13 शहरों में 10 अध्ययनों की एक श्रृंखला आयोजित की थी। इस अध्ययन से खुलासा हुआ कि इन शहरों में से कई, जिनमें मसूरी, दार्जिलिंग और काठमांडू जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल शामिल हैं, पानी की मांग-आपूर्ति के गहरे अंतर का सामना कर रहे हैं, जो कई जगह 70 फीसदी तक है और इसका मूल कारण इन इलाकों में जल सरिताओं-झरनों का तेजी से सूखना है। ठीक यही बात अगस्त 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट में कही गई थी। इसमें स्वीकार किया गया था कि आईएचआर में करीब 50 फीसदी झरने सूख रहे हैं।

झरना एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है, जहां से जल एक्वीफर्स (चट्टान की परत, जिसमें भूजल होता है) से पृथ्वी की सतह तक बहता है। पूरे भारत में लगभग पचास लाख झरने हैं, जिनमें से करीब तीस लाख अकेले आईएचआर में हैं। देश की बीस करोड़ से अधिक आबादी पानी के लिए झरनों पर निर्भर है। भारतीय हिमालय क्षेत्र के 12 राज्यों के 60,000 गांव हैं, जिनकी आबादी पांच करोड़ है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा इसके दायरे में हैं। असम और पश्चिम बंगाल भी आंशिक रूप से इसके तहत आते हैं। यहां की करीब 60 प्रतिशत आबादी जल संबंधी जरूरतों के लिए धाराओं पर निर्भर है।

उधर दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाटों में, कभी बारहमासी रहने वाले झरने मौसमी होते जा रहे हैं और इसका सीधा असर कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों पर पड़ रहा है। यहां झरनों के जलग्रहण क्षेत्र में बेपरवाही से लगाए जा रहे नलकूपों ने भी झरनों का रास्ता रोका है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में झरनों की संख्या पिछले 150 वर्षों में 360 से घटकर 60 रह गई। उत्तराखंड में नब्बे प्रतिशत पेयजल आपूर्ति झरनों पर निर्भर है, जबकि मेघालय में राज्य के सभी गांव पीने और सिंचाई के लिए झरनों का उपयोग करते हैं। ये झरने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक भी हैं।

झरनों के लगातार लुप्त होने या उनमें जल की मात्रा कम होने का सारा दोष जलवायु परिवर्तन पर नहीं मढ़ा जा सकता। अंधाधुंध पेड़ कटाई और निर्माण के कारण पहाड़ों को हो रहे नुकसान ने झरनों के नैसर्गिक मार्गों में व्यवधान पैदा किया है। नीति आयोग ने वर्ष 2018 में झरना संरक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना तैयार की और यह उसकी चार साल पुरानी एक रिपोर्ट पर आधारित थी, लेकिन बीते छह वर्षों में झरनों को बचाने के लिए कोई योजना बनी नहीं। उम्मीद है कि नए सर्वेक्षण की रिपोर्ट से झरनों को सहेजने की योजनाएं बनेंगी।

हालांकि यह जान कर सुखद लगेगा कि सिक्किम ने इस संकट को सन 2009 में ही भांप लिया था। इससे पहले सिक्किम में प्रति परिवार पानी का खर्च 3200 रुपये महीना था। 2013-14 में झरनों के आसपास 120 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढे बनाकर बारिश के पानी को संरक्षित करने पर काम शुरू किया और इसके 100 फीसदी परिणाम आने शुरू हो गए।

झरनों को लेकर सबसे अधिक बेपरवाही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, जो बीते पांच वर्षों में भूस्खलन के कारण तेजी से बिखर भी रहे हैं। इन राज्यों में झरनों के आसपास भूमि क्षरण कम करने, हरियाली बढ़ाने और मिट्टी के नैसर्गिक गुणों को बनाए रखने की कोई नीति बनाई नहीं गई। यह किसी से छिपा नहीं है कि मौसम चक्र तेजी से बदल रहा है। कहीं बारिश कम हो रही है, तो कहीं अचानक जरूरत से ज्यादा, फिर धरती का तापमान तो बढ़ ही रहा है। जरूरत इस बात की है कि नैसर्गिक जल सरिताओं और झरनों के कुछ दायरे में निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक हो, ऐसे स्थानों पर कोई बड़ी परियोजनाएं न लाई जाएं, जहां का पर्यावरणीय संतुलन झरनों से हो।